हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 1994

खण्ड–1, अंक–6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 7 मार्च , 1994

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(6)29
अताराकित प्र न एवम उतर	(6)30
वर्श 1994 का बजट पे ा करना	(6)51
वाक आउट	
वर्श 1994 का बजट पे ा करना (पुनरारम्भ)	(6)56

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 7 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में प्रातः 14.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर सहिबान, अब सवाल होगे।

Abolition of Octroal

***657 Shri Ram Bhajan Aggarwal:** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish Octroi in the State?

Minister of State for Local Govrnment (Chaudhri Dharambir Gauba): Yes Sir, There is a proposal to abolish tthe Octroi.

श्री राम भजन अग्रवालः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मंत्री माहेदय से जानना चाहूगा कि इस प्रोपोजल पर कब तक विचार हो जाएगा और कब तक निर्णय ले लिया जाएगा। दूसरे, इस विशय के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है यह नही, तो यह कब तक दी जाएगी?

चौधरी धर्मबीर सिंह गांबाः स्पीकर सर, इस बारे मे गवर्नमैट आफ इण्डिया ने एक कमेटी बनाई है जिसके चैयरमैन बगाल के चीफ मिनिस्टर है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी उसके मैम्बर है, यह कमेटी इस विशय पर गौर कर रही है कि मौडैलिटिज को कैसे एडाप्ट किया जाए, आक्ट्राय किस किस तरह से हटाया जाए और स्टेट के फाइनैस को कैसे ठीक किया जाए? एक कमेटी हैडेड बाद डायरैक्टर लोकल बाडीज है, जिसमे एल0आर0 का एक रिप्रैजेटेटिव है और एक ऐक्साइज एण्ड टैक्से ान का मैबर है। उसकी रिपोर्ट नही आई है। जब तक हाईपावर्ड कमेटी फेसला नही करेगी तब तक हम उस पर गौर नही कर सकते।

श्री राम भजन अग्रवालः स्पीकर सर, मे आपके माध्यम से मंत्री जी जानना चाहूगा कि स्टेट के अंदर आक्ट्राय की मद मे टोटल कितनी आमदनी होती है और उसको रिकवर करने के लिए सरकार को कितना खर्च करना पडता है?

चौधरी धर्मबी गाबाः स्पीकर सर, हमारा जो फरीदाबाद काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रे ान है उसका औक्ट्राय मिलाकर 42 करोड रूपये की आमदनी होती है। 30 करोड रूपया कमेटी से मिलता है और 12 करोड रूपया काम्पलैक्स से मिलता है। इस 42 करोड के लौस को कैसे पूरा किया जाए यह कमेटी के फेसले पर डिपैन्ड करता है। आक्ट्राय कलैक ान पर हमारा 30 से 40 प्रति ात तक खर्च होता है।

श्री राम भजन अग्रवालः स्पीकर सर, इस समय यू0पी0 गवर्नमैट ने आक्ट्राय एबोलि ा कर रखी है। पजाब, हरियाणा और अन्य स्टेटो मे आक्ट्राय अभी धी है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानता चाहता हू कि इन्होने जो हरियाणाा स्टेट मे आक्ट्राय खत्म करने की बात की है उनसे हरियाणा के मुलाजिमो ने एक तरह का भय है कि कही उनकी नौकरिया खत्म न हो जाए। मै जानना चाहता हू कि जो मुलाजिम इस फेसले से प्रभावति होगे उनके बारे मे सरकार क्या निर्णय लेगी।

चौधरी धर्मबी गाबाः स्पीकर सर, 3700 मुलाजिम की आक्ट्राय कलैक ान करते है। जो कमेटी बनाई गई है वह यह तो बताएगी ही कि फाइनैस रिसौसिज कैसे ठीक हो सकते है साथ ही इस बात की रिकमैडै ान भी भेजगी कि उन 3700 मुलाजिमो को हम कैसे ऐडजस्ट कर सकते है। इन कर्मचारियो को निकालने का सवाल ही नही है।

श्री राम भजन अग्रवालः क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगे कि आजकल जो रेट आफ आक्ट्राय है वह तर्कसगत है या नही है क्योकि यह किसी पर बहुत ज्यादा व किसी पर बहुत कम है?

श्री अध्यक्षः यह सप्लीमैटरी मेन क्वै ाचन से रिलेट नही करती।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूगा कि आक्ट्राय से स्टेट को कुल कितनी आमदनी होती है?

श्री अध्यक्षः यह तो अभी बता दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि यह जो एक कमेटी बनाई हुई है जिसके चेयरमैन बंगाल के मुख्यमत्री है उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और क्या उस के आने से पहले भी इसे ऐबोलि ा करने पर गौरा किया जा सकता है?

चौधरी धर्मबीर गाबाः स्पीकर सर, जो हाई पावर्ड कमेटी है, उसकी अभी एक मीटिग हुई है। मुख्यमंत्री जी के साथ वह मीटिग अटैन्ड करने मै भी गया था। अभी तो हाई पावर्ड कमेटी भी फेसला करेगी। हमने स्टेट लेवल पर जो कमेटी बनाई हुई है उसका जब तक हमारे पास ब्यौरा न आ जाए कि उन आदमियो को कैसे ऐडजस्ट करे, उससे पहले हम आक्ट्राय कैसे हटा सकते है?

श्री अमीर चन्द मक्कडः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी यह बताया है कि म्यूनिसिपैलिटी के 3700 कर्मचारी ऐसे है जो इस काम मे लगे हुए हैं। इनमे से ब्यौरेवार बताये कि क्लास–1 के कितने, क्लास–11 के कितने 11I के कितने तथा

क्लास 1V के कितने मुलाजिम है। इसके अलावा, फरीदाबाद काम्पलैक्स के इसमे कितने कर्मचारी है?

श्री अध्यक्ष: यह सूचना तो इनके पास अभी तैयार नही होगी। आप बैठिये।

Upgradation of Schools in the State

***665 Prof. Chhattar Singh Chauhan:** Will the Minister for Education be pleased to state whether any schools have been upgraded in the State during the year 1993-94, if so, the location thereof and the criterai adopted for the upgradation?

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana): Yes Sir, The List of such schools is placed as Annexure A and B on the Table of the House. The criterion adopted has been the need of the area.

ANNEXURE – A

Upgraded Schools during the year 1993-94

Sr.No.	Name of School	Upgraded to the level of
1	2	3
1	G.P.S Dhani, Raju (Hissar	Middle Standard
2.	G.P.S Banri (Karnal)	---do---
3.	G.P.S Shubhri (Ambala)	---do---

4.	G.P.S EBS Ghora Farm, Hisar	----do----
5.	G.P.S P.S Chakar (Sirsa)	---do---
6.	G.M.S Chakan Sirsa	High Level
7.	G.P.S Patuhera (Rewari)	Middelo Standard
8.	G.G.P.S Samegpur Bhiwani	---do--
9.	G.P.S Rampura Bhiwani	---do---
10.	G.P.S Jewra Hissar	---do---
11.	G.M.S Jewra Hisar	High Level
12.	G.P.S Mahu Gurgaon	Middel Standard
13.	G.M.S Mahu Gurgaon	High Level
14.	G.P.S Khapar Jind	Middle Standard
15.	G.G.P.S Boroda Jind	--do--
16.	G.M.S Kulan Hissar	High Level
17.	G.M.S Garnala Ambalal	--do--
18.	G.M.S Sultanpur Ambalal	--do--
19.	G.M.S Bhusali Karnal	--do--
20.	G.M.S Ahmedpur Darewala Godekan Sirsa	--do--

21.	G.M.S Karnauli Hissar	--do--
22.	G.M.S Alipu Khalsa Karnal	--do--
23.	G.M.S Ludesar (Sirsa)	--do--
24.	G.M.S Kwaratan Kaithal	--do--
25.	G.M.S Panihar Chak Hisar	--do--
26.	G.M.S Shahpur Jind	--do--
27.	G.H.S Barara Ambala	--do--
28.	G.G.H.S Sindhvi Khera Jind	Sr. Sec Level
29.	G.H.S Sarai Khawaja Faridabad	--do--
30.	G.G.H.S Adampur Hisar	--do--
31.	G.H.S Salwan Karnal	--do--
32.	G.H.S Kirtan Hissar	--do--
33.	G.G.H.S Nuran Khera Sonepat	--do--

List of 6 Shcools those were allowed to start w.e.f July, 1993, but the financial santion has not been issued so far

Sr.No.	Name of School	Upgraded to the level of

1	2	3
1	G.H.S Indri Karnal	Sr.Sec Level
2.	G.G.H.S Bhanswal Kalan Sonpat	---do---
3.	G.G.H.S Mokhra Rohtak	---do---
4.	G.P.S Kharaninti Rohtak	Middle Standard
5.	G.P.S Bassai Mohindergarh	---do---
6.	G.M.S Bassai Mohindergarh	High Standard

ANNEXURE –B

Sr. No.	**Name of Village Distt**	**Earlier Status**	**Upgraded Status**
1	2	3	4
1.	Achina (Bhiwani)	GGHS	GGSSS
2.	Mangali (Hissar)	GGHS	GGSSS
3.	Mulana (Ambala)	GGHS	GGSSS
4.	Budi Badli (Rohtak)	GGMS	GGSSS
5.	Kanina Mandi (M.Garh)	GGMS	GGHS

6.	Badopl (Hissar)	GGMS	GGHS
7.	Siswal (Hisar)	GGMS	GGHS
8.	Bhupnia (Rohtak)	GGMS	GGHS
9.	Akher Madanpur (Rohtak)	GGMS	GGHS
10.	Rawalwas Khurd (Hisar)	GGMS	GGHS
11.	Jui Khurd (Bhiwani)	GGMS	GGHS
12.	Devrala (Bhiwani)	GGMS	GGHS
13.	Gujarwas(M. Garh)	GGMS	GGHS
14.	Atta (Panipat)	GGMS	GGHS
15.	Dhatrath (Jind)	GGMS	GGHS
16.	Assdpur Nandnaur (Sonepat)	GGPS	GGMS
17.	Kuleri (Hissar)	GGPS	GGMS
18.	Matan (Rohtak)	GGPS	GGMS
19.	Khara Barwalal	GGPS	GGMS

	(Hisar)		
20.	Gorochhi (Hisar)	GGPS	GGMS
21.	Siswala (Hissar)	GGPS	GGMS
22.	Neoli Kalan (Hissar)	GGPS	GGMS
23.	Patan Tokes (Hissar)	GGPS	GGMS
24.	Silani (Rohtak)	GHC (Co-Edu)	GSSS (Co-Edu)
25.	Mandona (Ambala)	GHC (Co-Edu)	GSSS (Co-Edu)
26.	Sahlwas (Rohtak)	GHC (Co-Edu)	GSSS (Co-Edu)
27.	Badhra (Bhiwani)	GHC (Co-Edu)	GSSS (Co-Edu)
28.	Bewar Khana (Rohtak)	GHC (Co-Edu)	GSSS (Co-Edu)
29.	Gandhi Nagr Mangali (Hisar)	GHC (Co-Edu)	GSSS (Co-Edu)
30.	Dinar Pur (Ambalal)	GPS	GMS
31.	Rampur	GPS	GMS

	(Ambala)		
32.	Sewan Majra, Barara (Ambala)	GPS	GMS
33.	Saha (Ambala)	GGHS	10+2
34.	Ugala (Barara) Ambala	GHS	10+2
35.	Nagla Jattan (Ambala)	GMS	GHS
36.	Sardaheri Barara (Ambala)	GPS	GMS
37.	Gokal Garh, Barara (Ambala)	GHS	10+2
38.	Milak Khas, Bilaspur (Amabala)	GPS	GMS
39.	Pabnawa (Kaithal)	GGMS	GGHS
40.	Pharal (Kaithal)	GGMS	GGHS
41.	Tagra Hakimpur (Block Kalka)	GPS	GMS
42.	Karanpur, Block Kalka	GHS	GSSS

43.	Kheran Wali (Block Kalka)	GPS	GMS
44.	Dhamla, Block Kalka	GPS	GMS
45.	Ram Garh, Panchkula Block	GHS	GMS
46.	Jant (Rewari)	GMS	GHS

प्रो0 छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब मे अपग्रेडे ान के लिये यह कहा है "The criteria adopted has been the need of ath area." अगर अपग्रेडे ान के लिए अइटेरिया नीड आफ दी एरिया ही है, तो मै मत्री महोदय से आपके माध्यम से एक बात जानता चाहता हू । मेरी कास्टीच्यूएंसी मे दो ऐसे मिडल स्कूल है। एक बडसेरा का और दूसरा सांवड का है। हम इस बारे मे मंत्री महोदय से कई बार प्रार्थना भी कर चुके है। वहा पर एक हजार से ऊपर बच्चो की सख्या है वहा के लोगो ने कालेज के बराबर बिल्डिग बनाई हुई है। इसके अलावा, कुछ ऐसे प्राईमरी स्कूल्ज भी है जहां पर 500 से ऊपर विधार्थी है, क्या यह नीड आफ दी एरिया नही है? क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगे कि यह जो नीड आफ दी एरिया है, यह पोलीटीकल है या लोगो की मांग के अनुसार है?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजनीति भाब्द को बीच मे ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, ि ाक्ष

के क्षेत्र मे हम इनते फार्वर्ड है कि एक किलोमीटरी की परिधि मे तो प्राईमरी स्कूल्ज है। किसी बच्चे को एक किलोमीटर से ज्यादा प्राइमरी ि ाक्षा के लिये चलना नही पडता। 2.23 किलोमीटर से फालतू मिडल, हाई और हायर सैकेन्ड्री स्कूल के लिये चलना नही पडता। अगर कही पर स्कूल्ज अपग्रड कराने की आव यकता होती है। तो हम एग्जामिन कराते है और इस बारे मे विधायक सुझाव भी देते है। तभी स्कूज्ज अपग्रेड किये जाते है।

प्रो0 राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे 33 उन स्कूलो की लिस्ट दी है जिनके बारे मे फाईनै ीयल सैक ान ग्रान्ट कर दी गयी है लेकिन 46 विधालय ऐसे भी दिये है जिनमे अभी यह देनी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट मे अम्बाला और हिसार, दो जिलो का ही नाम ज्यादा है। मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से यह जानना चाहता हू कि जो यह लिस्ट है इसमे महेन्द्रगढ जिला रिवाडी जिला और रोहतक जिले के नाम ही नही है। क्या आने वाले साल मे इन जिलो मे जो कमी रह गयी है उसको रिकवर करने के लिए इनको प्राथमिकता दैगे?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, माननीय राम बिलास भार्मा जी ने हिसार और अम्बाला जिले की चर्चा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिसार वह जिला है जिसमे महिलाओ की जो परसेटेज आफ लिट्रेंसी है, वह काफी कम है। That is only 32.01% which is very much low. There is one more district

Jind, in which this percentage is lower than that of Hissar. But in Hisar Itself it is very much on the lower side. The Hon, Members himslef would see from the list that mostly the girls schools have been uprgaded and so far as Ambala District is concerned, this is hilly district. वहा के लोग बैकवर्ड है। उनकी आव यकता थी इसलिए वहा पर स्कूल अपग्रेड किये है। महेन्द्रगढ और रिवाडी जिले के कमी की जो बात इन्होने कही है उनके बारे मे बात यह है कि जैसे ही हमारे पास साधन उपलब्ध होगे, हर जिले की आव यकता को ध्यान मे रखा जायेगा।

डा0 राम प्रका ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि क्षेत्र हल्के की आव यकता को मददेनजर रखते हुए स्कूल अपग्रेड हुए है। अध्यक्ष महोदय, सारे कुरूक्षेत्र जिले मे कोई स्कूल अपग्रेड नही हुआ। बडे बडे कस्बे जैसे पीपली है, लाडवा है, और उभरी जो बहुत बडा गांव है। इन सब मे प्लस टु की सुविधा गांव के और भाहर के लोगो को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्पीकर साहब, भौक्षणिक सत्र आरम्भ होने वाला है। क्या इस क्षेत्र की जरूरत को ध्यान मे रखते हुए वहा पर स्कूलो को अपग्रेड करने की मंत्री महोदय कृपा करेगे?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि कुरूक्षेत्र जिले मे कोई स्कूल अपग्रेड नही किया गया है और वह जिला ि ाक्ष के क्षेत्र मे बहुत पिछडा हुआ है। मै सदन को बताना चाहता हू कि हरियाणा के सब से पहले अगर कोई वि वविधालय खुला था तो वह कुरूक्षेत्र मे खुला था। जहा

तक स्कूलो का सवाल है जैसा कि मैने पहले बताया है कि दो किलोमीटर या अढाई किलोमीटर से फालतू बडे से बडे स्कूल के लिए हमारे किसी बच्चे को चलना नही पडता है। अध्यक्ष महोदय, बजट, सदन के सामने आ रहा है और बजट मे जितना पैसा स्कूल को अपग्रेड करने के लिए रखा जाएगा उस के हिसाब से माननीय सदस्य के विचार को ध्यान मे रखते हुए स्कूलो को अपग्रेड करेगे।

डा0 राम प्रका ाः अध्यक्ष माहोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि दो अढाई मिलोमीटर से अधिक किसी बच्चे को नही चलना पडता। अगर चार किलोमीटर तक कोई स्कूल मेरे क्षेत्र मे अपग्रेड न हुआ तो क्या वहा पर स्कूल अपग्रेड करने पर विचार करेगे?

श्री फूल चन्द मुलानाः माननीय सदस्य अगर कोई ऐसा केस नोटिस मे लाएगे तो अव य ध्यान दिया जाएगा।

चौधरी बलवत सिह मैनाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि लडकियो के स्कूलो को अपग्रेउ करने मे प्राथमिकता दी जाती है। मेरे क्षेत्र मे इसमाइला एक गाव है वहा पर लडकियो का स्कूल है जिसमे प्लस टू के लिए कमरे बने हुए है। इस समय लडकियो को प्लस टू के लिए काफी दूर जाना पडता है। इस तरह से चुलाना गावं एक जगह है वहा भी यह स्थिति है। क्या मंन्डी महोदय इन जगहो को प्राथमिकता देकर वहा के स्कूलो को अपग्रेड करने की कृपा करेगे?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, मैने बताया है कि ि ाक्षा के क्षेत्र मे हरियाणा सरकार लडकियो को बहुत ही महत्व देती है क्योकि एक लडके को ि ाक्षा देने का मतलब है कि एक परिवार को ि ाक्षित करना। अध्यक्ष महोदय, जहा कही आव यकता होगी वहा पर हम प्राथिमकता देकर लडकियो के स्कूल को अपग्रेड करैगे।

चौधरी अजमत खाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो लिस्ट सदन मे रखी है उसको देखने से पता लगता है कि हिसार मे नौ स्कूल अपग्रेड किए है और करनाल तथा अम्बाला मे चार चार स्कूल अपग्रेड किए है परन्तु फरीदाबाद और गुडगांव मे एक एक किया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि लडके और लडकियो के स्कूलो को अपग्रेड करने का क्या आईटेरिया रखा है और क्या उस आईटेरिया को सरकार पूरा कर रही है ?

श्री फूल चन्द मुलानाः: अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने लिस्ट पढी नही है। इस लिस्ट मे हिसार है, करनाल है, रिवडी है, भिवानी है, जींद है, गुडगाव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है। हमने लडको के स्कूल भी अपग्रेड किए है। और लडकियो के भी किए है। लेकिन लडकियो के ज्याद अपग्रेड किए है और जहां एरिया की नोड है वहा लडको के स्कूल भी अपग्रेड किए है और जहां की नीड है वहा लडको के स्कूल भी अपग्रेड किए है।

चौधरी अजमत खाः स्पीकर साहब, हिसार मे नौ स्कूल अपग्रेड किए है, अम्बाला मे चार किए है और सिरसा मे चार अपग्रेड किए है, गुडगाव मे दो किए है और दरअसल वह एक ही जगह है माहू। फरीदाबाद मे एक स्कूल अपग्रेड किया है और कैथल भाहर मे किया है। क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेगे कि क्या दूसरी जगहो मे स्कूल अपग्रेड करने की जरूरत नही है, जहा अपने अपग्रेड नही किए है, क्या सरकार वहा स्कूल अपग्रेड करेगी?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, जहा कही आव यकता है और जो एरिया की नीड है उसको पूरी तरह से एग्जामिन करवाया है और आगे भी करवाएगे। जंहा तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि लडकियो के हुए है लडको के स्कूल अपग्रेड नही हुए है। इस सम्बन्ध मे मै कहना चाहता हू कि आने वाले बजट मे जितना प्रावधान सदन करेगा उसके मुताबिक स्कूल अपग्रेड करेगे।

श्री सतबीर सिंह कादियानः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि वर्श 1991–92, 1992–93 और 1993–94 मे कुल कितने स्कूल अपग्रेड किए और 23.3.1991 को जो 350 स्कूल अपग्रेड किए गए थे, उनमे से कितने स्कूलो को अपग्रेड करने का असली जामा पहनाया गया था?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, सातवे फाइव ईयर प्लान मे हमारा टारगैट केवल पांच सौ स्कूलो को अपग्रेड करने का थ लेनिक हमने पांच सौ दस स्कूल अपग्रेड किए। माननीय सदस्य ने पूछा है कि डिफरैन्ट सालो मे कितने स्कूल अपग्रेड किए, उस बारे मे मै बताना चाहता हू कि 1991–92 मे 29 स्कूल प्राईमरी से मिडल अपग्रेड किए, 63 स्कूल मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड किए और 72 स्कूल हाई से प्लस टू अपग्रेड किए। 1992–93 मे प्राईमरी से मिडल स्कूल 56, मिडल से हाई स्कूल 63, और 30 हाई से प्लस टू अप ग्रेड किये गये है। साथ मे इन्होने कहा कि जिनका दर्ज अप ग्रेड किया गया है, क्या उनको सभी प्रकार की सुविधाए दी गई है। स्पकीर साहब, जिनको अभ अपग्रेड किया गया है उनकी क्लासिय अप्रैल से भुरू होगी और जो स्कूल पहले अपग्रेड कर दिये गये है उनकी क्लासिज भुरू कर दी गई है।

प्रो0 छतर सिंह चौहाना: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि स्कूल्ज अपग्रेड करते वक्त पोलिटीकरल आईटेरिया नही देखा जाता लेकिन यह जो लिस्ट है, यह साबित करती है कि हिसार और अम्बाला जिलो मे स्कूल्ज की अपग्रेडता सब से अधिक हुई है। इस से साफ जाहिर होता है कि स्कूल्ज को अपग्रेड करते वक्त आम लोगों की जरूरियात को नजर अन्दाज कर दिया गया है और पोलिटीकल आईटेरिया का ही आधारी माना गया है। मै उन से यह जानना चाहता हू कि 1991–92, 1992–93 व 1993–94

मे भिवानी जिले मे लडके और लडकियो के स्कूलो की तरफ सरकार ने खास ध्यान दिया है। गवर्नमैट मिडल स्कूल बहेसर, गर्वनमैट मिडल सकूल सांवड, जिनको अपनी बिलडिग्ज भी है और कालेज के समान है। लगभग 1000 के करीब बच्चे भी वहां पर है क्या ऐसे स्कूलो के लिए सरकार का जो आईटेरिया है, वह लागू नही होता है? क्या सरकार इन स्कूलो को भी उसी आईटेरिया के तहत नापेगी?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यहा पर हिसार और अम्बाला जिलो की काफी चर्चा हुई है, कि सारे हरियाणा के अन्दर इन दो जिलो मे स्कूल्ज को सब से ज्यादा अपग्रेड किया गया है। हिसार जिला मे मुताल्लिक इनके दिल मे इससिलिए सन्देह हो रहा है, क्योकि वह मुख्यमंत्री का जिला है लेकिन ऐसी कोई बातचीत नही है। हिसार जिला हरियाणा के अन्दर सब से बडा जिला है। उसमे भी लगभग इनती ही असैम्बली सीटे है। मेरा इतना ही कहना है कि जो जिला ऐजूके ान के लिाह से पिछडा हुआ हो, उसका खासतौर से ध्यान रखा जाता है। वैसे जिला के साथ सरकार कोई भेदभाव की नीति नही बरतती है।

Family Planning Programme

***678 Shri Jai Parksh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether any finacial assistacne has been received from the Central Govt. to implement the family planning programme in the State during the years 1992-93 and 1993-94 todate; togetherw the measure adopted by the Govt. to make the family planning programme a success; and

(b) whether the target; if any, fixed for the pupose has been achieved; if so, upto what extent?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती भाान्ति देवी राठी): वान्छित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) परिवर कल्याण कार्यक्रम को चलाने के लिए भात प्रति ात वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वर्श 1992–93 मे 2864.11 लाख रूपये की धन रा ि ा प्राप्त हुई थी (1643.27 लाख नकद, 431.91 लाख वस्तुओ के रूप मे तथा 788. 93 लाख रूपये वि व बैक परियोजना के अधीन) वर्श 1993–94 के दौरान अब तक (जनवरी, 1994) 2435.49 लाख रूपये की रा ि ा प्राप्त हो चुकी है। इसमे 799.84 लाख जो वि व बैक परियोजना के अधीन मिले है भी सम्मिलत है।

इस कार्य{म को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है:–

1. यह कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से लागू किया जा रहा है।

2. सभी जिलो के जनसख्या के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गये है।

3. अस्थाई तथा स्थाई तरीको की सुविधाए उप केन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा सामान्य हस्पतालो मे उपलब्ध है।

4. वि व बैक परियोजना के अन्तर्गत स्वास्थय विभाग के स्टाफ को छोटे परिवार के नार्म अपनाने के लिए लोगो को मांग द र्शन कराने के लिए उचित प्रि ाक्षण दिया गया है।

5. लोगो को छोटे परिवार के लिए प्रेरित करने के लिए सभी विभागो मे सहयोग लिया जा रहा है।

6. भाहरी जनता की देखभाल के लिए 37 पोस्ट पार्टम केन्द्र कार्य कर रहे है।

7. मैडिकल कालेज रोहतक मे डाक्टरो को प्रि ाक्षण दिया जा रहा है।

8. राज्य मे स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी सस्थाओ को इस कार्य मे भागीदार बनाने के लिएा राज्य मे स्टैडिग कमेटी आन बालन्ट्री एक ान (स्कोवा) बनाई गई है।

9. 1000 जनसख्या से अधिक वाले सभी गावो मे महिला स्वास्थय संघ बनाए गए है जो कि योग्य दम्पतियो को छोटे

परिवार के लिए प्रेरित करते हैं राज्य मे 2346 महिला स्वास्थय संघ कार्यरत है।

10. वर्श 1981 की जनगणना अनुसार जिला भिवानी, जहा पर जन्मदर सभी जिलो मे अधिक था परिवार कल्याण सेवाए तथा मातृ एवम ि ा ु सेवाओ को सुधारने के लिए एक वि ोश स्कीम (सो ाल सेफटी नैट स्कीम) चालू की गई है।

11. बच्चो के बचाव के लिए और माताओ के स्वास्थय के लिए सभी बच्चो तथा माताओ को टीके लगाए जा रहे है।

(ख) इस कार्यक्रम के लक्ष्य तथा प्राप्तियां निम्न प्रकार से है:–

1992–93

तरीके	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रति ातता
बन्धीकरण	104000	98047	94.3
लूप निवेशण	183000	133133	72.8
निरोध प्रयोगकर्ता	500000	427577	85.5
गर्भ निरोधक गोलियो की	37000	31461	85.0

प्रयोगकर्ता			

1993—94 जनवरी 1994

तक

तरीके	लक्ष्य	प्रोपो ानेट लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रति ातता
बन्धीकरण	11000	83600	78871	94.3
लूप निवेशण	183000	139080	110292	79.3
निरोध प्रयोगकर्ता	637000	530830	380146	71.6
गर्भ निरोधक गोलियो की प्रयोगकर्ता	50000	41670	30962	74.3

श्री जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्र न के उतर मे माननीय मंत्री महोदय ने सदन की पटल पर जो सूचना रखी है, उसी के सन्दर्भ मे, मै आपके द्वारा उन से यह जानना चाहता हू कि जो पैसा भारत सरकार व वर्ल्ड बैक की सहायता से राज्य सरकार को मिला है उसमे कितना कितना पैसा जिला वाईज अलौट किया गया है और कितना कितना पैसा खर्च हुआ है?

श्रीमती भाान्ति देवी राठीः स्पीकर सर, जितना पैसा केन्द्र सरकार व वर्ल्ड बैक से मिला था वह सारा जनसख्या के आधार पर सभी जिलों मे आबटित कर दिया गया है।

श्री जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदया ने बताना कि जनसख्या के आधार पर पैसे आबटन कर दिया गया है। मै उन से यह जानना चाहता हू कि इस के लिए केवल जनसख्या के आईटेरिया को आधार माना गया है या किसी और बात को भी इसके लिये सरकार ने आधार माना है?

श्रीमती भाान्ति देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन केवल मात्र जनसख्या का आधार ही होता है और उसी हिसाब से पैसा अलौट किया जाता है।

श्री जय प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेगी कि जो पैसा हमे भारत सरकार से और वर्ल्ड बैंक की सहायता से मिला है उस के हिसाब से जनसख्या दर मे कितने परसन्टेज की कमी आई है ?

श्रीमती भाान्ति देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, जंहा तक जनसख्या दर मे कमी का सवाल है, उसमे कुछ कमी आई है लेकिन यह कमी कम है। हरियाणा के हालात को देखते हुए यह कमी बहुत कम है। मै यह समझती हू कि इसमे और ज्यादा कमी आनी चाहिये थे हमारे हरियाणा के अन्दर बच्चियो की भाादी कम उमर मे कर देते है जिसकी ऐवरेज 17.8 है और भारत सरकार की

18.8 है। एक प्रान्त केरल ऐसा है जिसकी 21 द ामवल कुछ है। इसके लिए कुछ दूसरे दो तीन कारण और भी है। हम व्यक्ति के मन मे चाह रहती है कि जहां उसके बेटी हुई है बेटा भी हैं। हमारे समाज की कुछ व्यक्ति के मन मे चाह रहती है कि जहां उसके बेटी हुई है बेटा भी हो। हमारे समाज की कुछ ऐसी विचारधारा बन गई है। स्पीकर साहब, इस बारे मे थोडा डिटेल मे बताना पडेगा। आप जानते है कि जिस वक्त परिवार नियोजन लागू हुआ था तो हमारे हरियाणा मे ही कितनी हाहाकार मची थी और उससे कुछ सरकारे भी तथा कुछ व्यक्ति वि ोश भी प्रभावित हुए थे। लेकिन आज मै यह दावे के साथ कह सकती हू कि परिवार नियोजन जिस तेजी से चल रहा है और युद्ध स्तर पर चल रहा है उसको सभी जानते है । आज हमारे बुद्धि जीवी, उच्च और मध्यम वर्ग के लोग पूरी तरह से परिवार नियोजन को अपना चुके है, चाहे स्थाई या अस्थाई तरीके से। आज केवल एक कोताही बाकी है, वह है साक्षरता की, वि ोश तौर पर हमारी महिलाएं पढ लिखी नही है। उन के मन मे एक चाह रहती है कि बच्चे ज्यादा हो और उनमे लडके अव य हो। इसके अतिरिक्त हम लापरवाही बरतते है कि जो साधन नव दम्पतियों को इसके लिए बताए जाते है उनको अपनाने के लिए या प्रयोग करने के लिए वे कोताही बरतते है। यह एक बहुत बडा कारण है। इसलिए स्थिति कन्ट्रोल नही हो रही है। यह कभी भी ग्रामीण क्षेत्रो मे है। हमारा स्वास्थय विभाग इसके लिए पूरे उपाय कर रहा है। जिससे हम जल्द से जल्द इस पर और कन्ट्रोल कर पांए।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसालाः अध्यक्ष महोदय, मै बहिन जी ने कहना चाहता हू कि दे ा और प्रदे ा मे बढती हुई जनसख्या की भीड एक विस्फोटक स्थिति धारण कर चूकी है। प्राय गावो के जो नौजवान है वे हम सभी विधायको के पास नौकरी मागने आते है। उनसे हम पूछते है कि आपके पास जमीन कितनी है तो वे कहते है कि बिल्कुल भी नही है। वे कहते है कि हम या तो पुलिस मे भरती करवा दे या पटवारी बना दे, हमारे 4–5 बच्चे है। बहिन जी जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम बताया है या तो कुछ भी नही है मै मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हू कि जिस तरह से दूसरी बातो की तरह हरियाणा मे लीड की है उस तरह से इस मामले मे हम क्यो नही करते। चीन मे फेमिली प्लानिग बहुत भारी कामयाब हुआ है। मै चाहता हू कि हमारे सदन के सदस्यो की एक कमेटी बनाई जाए जिसमे अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ जांए। वह स्टडी टीम चीन मे भेजी जाए और उनका सिस्टम हरियाणा मे लागू किया जाए ताकि इस स्थिति पर काबू किया जाए। बढती हुई जनसख्या ला एण्ड आर्डर के लिए बडी भारी समस्या है और यह दे ा के अन्दर मौजूदा पोलिटिकल सिस्टम के सामने एक चुनौती है। तो मै जानता चाहता हू कि क्या चीन के पैट्रन पर हरियाणा के अन्दर भी इस तरह का फूल प्रूफ फेमिली प्लानिग सिस्टम एडाप्ट करेगे और ऐसा करके सारे दे ा के अन्दर मिसाल कायम करेगे।

श्रीमती भान्ति देवी राठीः स्पीकर साहब, मेरे भाई बिसला साहब ने एक बहुत ही अच्छा और सुन्दर सुझाव रखा है। हमारे राश्ट्र के सामने बढती हुई जनसख्याा की एक बडी भारी चुनौती है। इनकी यह बात अच्छी है। मुख्यमंत्री जी को इसमे क्या आपति हो सकती है कि कोई ऐसी टीम बना दी जाए, जो दे ाो मे जनसख्या कम है उनका वह टीम सर्वे कर सकता है। मै माननीय सदस्य के इस सुझाव का स्वाबत करती हू।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, हमारे माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह बिसला ने सदन के सामने फेमिल प्लानिग के बारे मे एक सुझाव रखा है। मै मंत्री महोदय से कहना चाहूगा कि वे इस बारे मे मोहम्मद इलियास, भाकरूल्ला खां, और अजमत खां ने राय ले ले कि वे इससे सहमत है या नही। (हंसी)

श्रीमती भान्ति देवी राठीः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य राम बिलास भार्मा जी ने वाकई मे दुखती रग को छूआ है। हिन्दू के लिए तो यह बैन है कि वह एक ही भाादी करवा सकता है लेकिन मुसलमान के लिए यह बैन नही है। मुसलमान चाहे कितनी भाादिया करवा ले। यादि कोई आदमी भादिया ज्यादा करवाता है तो नैचूरली उसके बच्चे भी ज्यादा हो होगे। मै हरियाणा से और खास करके विधायको से अनुरोध करूगी कि आपको इस प्रक्रिया मे कम से कम काम करना चाहिए और आपका हिसाब किताब ठीक से चलना चाहिए। (हंसी)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य भाई राम बिलास भार्मा ने जो बात छेडी है वह किसी और तरह से खत्म हो सकती है। मुस्लिम भाई भाादिया चाहे तीन या चार कर ले हमे कोई एतराज नही लेकिन फेमिल प्लानिग के जरिए बच्चो के बर्थ पर तो कट्रोल किया जा सकता है। यदि मुस्लिम भाई बर्थ पर कंट्रोल कर लेते है तो यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। भाादियां चाहे तीन चार कर ले लेकिन बच्चे दो से फालतू न हो। स्पीकर साहब, चूकि अभी बिसला साहब ने जिस बात का जिकर किया था, उसमे सीरियस स्टैप्स उठाने की बात है। इनसैटिव और डिसइनसैटिव की बात है। जो फेमिल प्लानिग एडोप्ट करते है, जिनके एक या दो बच्चे होते है उनको इनसैटिव दिया जाए और यदि इससे जयादा बच्चे होते है तो उसको डिसइनसैटिव किया जाए। पहले चाहे किसी के कितने ही बच्चे है लेकिन आंइदा से एक डैड लाईन मुकरर्र कर दी जाए कि एक या दो बच्चे से ज्यादा जिसके बच्चे हो, उनको डिसइनसैटिव दिया जाए। क्या सरकार इस तरह की स्कीम का कोई विचार रखती है?

श्रीमती भान्ति देवी राठीः स्पीकर साहब, भाई सम्पत सिंह जो ने जो सुझाव दिया है हरियाणा सरकार आलरेडी वह इनसैटिव दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी और वित मंत्री जी ने पिछले दिनो एम्पलायड महिलाओ को जिनके दो बच्चे है, 6 महीने की छुटटी देने का इनसैटिव दिया है ताकि वे महिलांए अपने बच्चा का पालन पोशण ठीक ढग से कर सके। अपने दूध से अपने बच्चो

का पालन कर सके। जहां तक इनके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, उस बारे मे मैने पहले ही बता दिया है कि महिलाओ मे साक्षरता का अभाव है, उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने लडकियो की बी0ए0 तक की ि ाक्षा फ्री की है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अभी बहन जी ने कर्मचारी महिलाओ को इनसैटिव देने के बारे मे बताया है। मै भी इनकी बात को एडमिट करता हू। कि एम्पलायड महिलाएं आलरेडी फेमिल प्लानिग की स्कीम को एडौप्ट कर रही है, उनको यह इनसैटिव दिया जा रहा है। लेकिन उनसे जनसख्ंया मे कमी होने का कोई लम्बा चौडा फर्क नही पडता। हमारे प्रदे ा की डेढ करोड जनता मे से जो महिलाए सर्विस करता है उनकी संख्या तो बहुत थोडी है। मेरा मतलब तो उन महिलाओ को इनसैटिव देने के बारे मे था जो आम गरीब लोग है, अनपढ लोग है, लेबर तबका है क्या सरकार द्वारा उनको कोई इनसैटिव या डिसइनसैटिव देने की कोई स्कीम लागू की जाएगी।

श्रीमती भान्ति देवी राठीः स्पीकर साहब, देहातो मे जो महिलाओ सर्विस करती है उनमे से पांच महिलाओ एक्स औफिसियो मैम्बर और 10 महिलाओ बिल्कुल देहाती क्षेत्र को मिला कर 15 महिलाओ की एक टीम बनाई गई है। उनकी गांव गांव मे प्रति मास बैठक होती है। यह टीम अनपढ महिलाओ की एजुकेट करती है। व अनपढ महिलओ को बताती है कि परिवार नियोजन के कितने फायदे है । कम बच्चे होगे तो उनको अच्छे ढंग से

पढाया जा सकता है उनका पालन पोशण सही तरीके से किया जा सकता है। यह टीम इस तरह से काम करती है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेन्टरी मैने की है, उसको भाायद बहन जी समझ नही पाई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे सस्ते अनाज की दुकाने है, परमिटस देने की बात है या और किसी प्रकार के कोटे देने की बात है उनको ऐसे इनसैटिव दिए जांए तो आबादी को बढने से रोकने मे सरकार द्वारा लागू की गई पालिसी का पालन करे और जो ऐसा न करे उनको डिसइनसैटिव किया जाए ताकि आबादी पर कन्ट्रोल पाया जा सके। मंत्री महोदय लिखे लोग तो इन सारी बातो को समझ गए है और जो अनपढ और गरीब लोग है, उनमे अभी इनती जागरूकता नही आई है मै मंत्री महोदया से जानना चाहता हू कि क्या चीन की तहस जनसख्या पर अकु ा लगने के लिए कोई इनसैटिव व डिसनसैटिव की स्कीम सरकार के विचारधीन है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सारा दे ा बढती हुई आबादी से चिन्तित है और भारत सरकार ने इस बारे मे कई दफा विचार किया है कि किस तरह बढती हुई जनसख्या पर रोक लगाई जा सकती है, इस पर गहराई से अध्ययन चल रहा है और हम भी कोि ा ा कर रहे है कि बढती हुई आबादी पर रोक लगनी चाहिए। यदि आबादी पर रोक नही लगेगे तो फि हम चाहे कितने ही विकास के काम कर ले, उनका कोई फायदा नही हो पाएगा। हम पंचायत एक्ट मे भी कुछ तरमीम

करने जा रहे है और यह अमैडमैट इसी सै ान मे ला रहे है। जिस प्रकार से इन्होने चाइना का जिकर किया, उस बारे मे इनका कहना ठीक है कि चाइना ने इस पर काफी हद तक काबू पाया है। मै भी अगले महीने चाइना जा रहा हू हम वहा पर देखगे कि उन्होने इस बढती हुई आबादी पर कैसे काबू पाया। यदि वह सिस्टम हमे ठीक लगा तो उस बारे मे सबसे बातचीत करके और हाउस की सहमति से यानी असैम्बली मे बात करके उसे लागू करने की कोि ा ा करेगे ताकि आबादी पर कन्ट्रोल हो सके।

Syshon on Sajuma Minor

***687 @ Chaudhri Bharath Singh:** Will the Minister for irrigation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a syphon on the Sajuma Minor; and

(b) if so, the time by which the above said syphon is likely to be constructed?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra):

(a) Yes

(b) The work shall be taken up in hand immediately subject to availability of funds.

श्री सतबीर सिह कादायानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने न तो जवाब हां मे दिया न तो ना मे दिया है दूसरी

तरफ कहते है कि धन की उपलब्धि पर यह काम किया जायेगा। मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पेसिफिक समय पूछना चाहता हू कि इस साईफन का काम एक साल मे या दो साल मे यानी कब तक पूरा कर दिया जायेगा? ये कोई टाईम बाउंउ समय बता दे।

चौधरी जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा कि धन की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। लेकिन मै इनको बताना चाहता हू कि वर्श 1994–95 मे इसके लिए सिचाई विभाग फण्डज ईयर मार्क कर रहा है। इसको हम 1994–95 बना देगे।

Vacant Posts of Patwaris

***670 Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whehter any post of Patwaris are lying vacant as at present in district Faridabad; if so, the number thereof togetherwith the time by which the said posts are likely to be filled up?

राजस्व मंत्री (श्री निर्मल सिंह): हां जी इस समय पटवारियो के 105 पद रिक्त है जिन्हे भरने मे लगभग दो वर्श का समय लगेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि जिला फरीदाबाद मे 105 पटवारियो के पद रिक्त पडे है। जब अकेले जिला फरीदाबाद मे 105 पद पटवारियो के रिक्त पडे है तो फिर सारे हरियाणा मे तो पता नही कितने पद रिक्त होगे? पटवारियो के रिक्त पद होने के कारण गांव भाहर के लोगो

ने अपनी जमीन से सबधित पेपर लेने मे बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। दूसरे मै इनके ध्यान मे लाना चाहता हू कि इस मौजूदा सरकार ने पीछे 540 पटावारी, जो लगे हुए थे, उनको हटा दिया है। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या पटवारी की कमी को ध्यान मे रखते हुए, इन निकाले हुए पटवारियो को दुबार नौकरी मे लेने पर सरकार विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि अगर मंत्री महोदय यह समझते है कि पटवारियो की भर्ती मे दो साल का समय लग जाएगा तो दो वर्श का समय बहुत ज्यादा है, इसलिए एम0ए0 या बी0ए0 पास नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे है, क्या उनमे मे कुछ पटवारियो के पदो पर लगाने बारे सरकार विचार करेगी? स्पीकर साहब, हो सकता है इसमे सरकार को बहुत भारी समस्या हो। स्पीकर साहब, पटवारियो की भर्ती सारी स्टेड मे हुई है। और एक एक लाख रूपये की बोली इन पोस्टो मे लिए लगी है।

अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि क्या पटवारियो की पोस्टस भरने के लिए भीघ्रति ीघ्र कार्यवाह करेगी?

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है जो पटवारी भर्ती किए गए थे, उनको सरकार ने हटा दिया, इसके जवाब मे मै बताना चाहूगा कि 465 पटवारियो को

नियुक्ति सरकार ने नही बल्कि सुप्रीमकोर्ट ने इस बात पर रदद कर दी है। कि एक ही क्षेत्र के ज्यादा लोगो की भर्ती की गई थी इसलिए भाक पैदा होता है कि जो भर्ती की गई है वह कायदे कानून के मुताबिक नही की गई है। स्पीकर साहब, इस बारे मे सरकार ने काफी नर्मी का रवैया बरतते हुए री एडवटाईजमैट मे, इन लोगो को एज मे रिलैक्से ान दे कर इन्टरवयू पर बुलाये जाने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही जो एम0ए0 या बी0ए0 पास बच्चे है, उनसे पटवारियो का काम नही लिया जा सकता। हम पटवारीयो की सिलक ान तो महीने दो महीने मे करवा लेगे लेकिन जो 2 वर्श का समय मैने बताया है वह इन पटवारियो की ट्रेनिग का समय भाामिल करके बताया है।

श्री कर्ण सिह दलालः स्पीकर साहब, दो साल का अर्सा बहुत ज्यादा अर्सा है। और इस अर्से मे बहुत से भोले भाले लोग दफतरो मे चक्कर काटते रहेगे और उनको वंहा पर कोई जवाब देने वाला भी नही मिलेगा जिसकी वजस से फील्ड मे लोगो को बहुत भारी परे ाानी का सामना करना पडेगा। इसलिए मै दोबारा मंत्री जी से यह जानना चाहूगा कि क्या बी0ए0 या एम0ए0 पास बेरोजगार युवको को इस काम के लिए भर्ती किया जाएगा?

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूगा कि ट्रेनिग दिए किसी भी व्यक्ति को फील्ड मे पटवारी नही लगाया जा सकता क्योकि उसकी बहुत स्पैसिफिक नेचर का काम करना पडता है जैसे खसरा, फर्द,

गिरदावरी आदि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिनको करने के लिए आदकी का ट्रेंड होना निहायत जरूरी है और बिना ट्रैनिग के यह काम नही हो सकता है किसी भी बी0ए0 या एम0ए0 नौजवान को बिना ट्रैनिग के यह काम नही दिया जा सकात। जो दो साल का समय मैने बताया है, उसमे ट्रैनिंग पीरियड भी भाामिल है भर्ती तो हम बहुत ही जल्दी कर लेगे।

श्री अध्यक्षः जो रिटायर्ड पटवारी है क्या चलाने के लिए इनको दोबार पटवारी लगाया जा सकता है?

श्री निर्मल सिहंः अध्यक्ष महोदय, जो रिटायर्ड पटवारी है उनको लगाने के बारे मे गौर किया जा सकता हैं पहले भी रिटायर्ड पटवारियो को सेवा मे लिया गया था और अगर जरूरत पडी तो इस पर विचार कर लिया जाएगा।

Cases of Rape/Murder etc Registered in the State

***726 Prof. Sampat Singh:** Will the Minister be pleased to state-

(a) the number of cases of murder, rape, kinnapping/ adduction registered in the State during the year 1993-94;

(b) the number of cases out of those as referred to in part (a) above relating to minors and the persons belonging to Scheduled Castes and Back ward Classes;

(c) the numer of cases out of those referred to in part (a) above in which accused have been punished; and

(d) the numer of cases as referred to above which are declared untraced together with the cases which are under trial in the Courts?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

भाग (क)

अपराध का भीर्श	दर्ज हुए मुकदमे	
	1993	1994 (31.1.1994)
हत्या	603	34
बलात्कार	229	16
अपहरण	315	35

उपरोक्त भाग (क) मे से

चौधरी भजन लालः

भाग (ख)

	अवयस्क	अनुसूचित जातियो	पिछडी जातियो
	1993 1994	1993 1994	1993 1994
हत्या	23	38 4	32 ...
बलात्कार	54 5	47 1	21 1
अपहरण	47 3	28 2	24 1

भाग (ग)

	दोशी सजा हुए
हत्या	3
बलात्कार	1
अपहरण	2

भाग (घ)

	अदमपता		न्यायालय मे	

			विचाराधीन	
	1993	1994	1993	1994
हत्या	42	.....	378	1
बलात्कार	1	....	189	....
अपहरण	19	.....	142	1

प्रो0 सम्पत सिहः अध्यक्ष महोदय, अपने जवाब मे मुख्यंमत्री जवाब मे मुख्यमंत्री जी ने मर्डर, किडनैपिग, एब्डक्टिग और रेप के फिगर्ज दिए है, जिसमे अनुसूचित जातियो, पिछडे वर्गो अवयस्को के नम्बर्ज दिए गए है। इसमे माइनर्ज बी0सी0 और अनूसूचित जाति के मर्डर के केसिज 97 है, रेप के 129 है और किडनैपिग के 105 है। इस प्रकार बलात्कार और अपहरण के मामले मे डिप्रैस्ट क्लास है, उनकी सख्या ज्यादा है। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूगा कि मर्डर के जो 603 मुकददमे दर्ज हुए है, उनमे किलिग्ज कितनी हुई है और इसमे से गिरफतारियो कितनी हुई है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहा तक क्राईम्ज की रोकथाम का ताल्लुक है, सरकार के भरसक प्रयास रहते है कि कोई भी क्राइम न हो। अध्यक्ष महोदय, यह तो आप भी जानते है कि आज आबादी इतनी बढ गई है कि क्राईम्ज होते है। यह तो इनके राज मे भी होते है। यह तो इनके राज मे भी होतें थे और

आज भी होते है। लेकिन हमारी सरकार भरसक प्रयास होते है कि अगर कोई क्राईम होता है तो उसकी फोरन जांच हो। अध्यक्ष महोदय, हत्या के 1993 मे जो केसिज हुए है, इनमे सारी की सारी गिरफतारी हुई है। इसमे कुल 1314 गिरफतार हुए है, चालान 1150 का हुआ है सजा दो को हुई है बरी 101 हुए है और 1047 केसिज कोर्ट मे विचाराधीन है।

इसी तरह से बलात्कार के केसिज मे 338 गिरफतारिया हुई है 322 चालान हुए है, 23 बरी हुए है और 298 केसिज कोर्ट मे पैडिग है। अपहरण के केसो म 394 गिरफतारिया हुई है जिनमे से से 336 चालान हुए है, 2 को सजा हुई है 19 बरी हुए है और 315 केसिज कोर्ट मे पैडिग है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने यह पूछा था कि 603 हत्या के जो केसिज है, इनमे कितने किलिग्ज हुई है। दूसरे इन्होने कहा है कि सारे अरैस्ट कर लिए है। और इन्होने जो ब्यान पार्ट डी मे दिया है उसके मुताबिक अध्यक्ष महोदय, ये अनट्रेस्ड ही रह गए है इसलिए इनमे गिरफतारिये कैसे हो सकती है? मै इनसे यह पूछना चाहता हू कि जहां पर दोशी अनट्रैस्ड है वहा पर गिरफतारियां कर ली गई है, क्या यह ठीक है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये भी होम मिनिस्टर रहे है और इनको पता होना चाहिए कि अनट्रैस्ड किसे कहते है। मै इनको बता देता हू कि केस तो दर्ज हो गया लेकिन

असलियत मे वह मुजरिम नही है या कोई खुदक ाी कर ले तो वह मुकदमा 302 के तहत दर्ज होता हैं। जैसा कि अभी मैने बताया कि जितने केसिज है, उनमे सारे के सारे मुलजिम पकडे गए है और उनके विरूद्ध अदालत मे केस है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै तो यह पूछ रहा हू कि ये जो 603 केसिज है उनमे कितने मारे गए है यह बता दे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने जो जवाब दिया है वह इन्होने पढा नही है। साथ ही सम्पत जी ने टोटल किलिग के बारे मे पूछा है, वह इन्फर्मे ान हमारे पास नही है, हम बाद मे इनको भिजवा देगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है कि सारे दे ा के मुकाबले हमारे प्रदे ा मे कानून एवम व्यवस्थ की स्थिति बहुत अच्छी ही नही बल्कि सबसे अच्छी है। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदे ा का जिला फरीदाबाद है, उसके साथ दिल्ली, उतरप्रदे ा और राजस्थान की सीमाए लगती है। जो राजस्थान और उतरप्रदे ा मे अपहरण धन्धा करते है, उसका प्रभाव हमारे जिले पर पडता है वि ोशकर जो इन्डस्ट्रलिस्टस जिन्होने बडी मेहनत से नाम रो ान किया है, जैसे श्री नन्दा है जिन्होने बहुत से लोगो को रोजगार दिया हुआ है दूसरे श्री लखानी जी है, ये ऐसे उधोगपति है जिन पर सभी हरियाणवासियो को फरख है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे उधोगपतियो को रोजाना

चिट्ठियां आती है कि सबका अपहरण कर लेगे या आप इतना पैसा न दे दो, यह दे दो वह दे दो। जितने भी वहां पर बडे बिजनैसमैन है, उनको चिठिठंया आती रहती है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से वहा पर छोटी मोटी घटनाए अपहरण की होती रहती है। हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि सरकार ने उन लोगो को सुरक्षा दी हुई है लेकिन पूरी सुरक्ष नही है। क्या सरकार इडस्ट्रिलिटस को या बिजनैसमैन को उनकी लाइफ और प्रोपर्टी सुरक्षित रखने के लिए कोई ऐसा फूलप्रूफ सिस्टम बनाने का इरादा रखती है? जैसे उतर प्रदे ा के इस तरह से की घटनाए होती है कि किसी को एक लाख मे उठा लिया, किसी को 20 लाख मे उठा लिया, ऐसी घटनाए यहा न हो। इसलिए सरकार को बोर्डर के थानो मे मजबुती प्रदान करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर पर मेरे हल्के मे छायसा थाना है। इसका एरिया जमुना के साथ साथ 35 किलोमीटर लगता है। इस थाने मे कोई भी ढग की जीप नही है। एक जीप है, वह भ टूटी हुई है। हमने कई बार कहा है कि वहा पर एक जिप्सी दी जानी चाहिए। वह थानेदार उस टूटी हुई जीप को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए वहा ज्यादा धन, बढिया हथियार और जिप्सी बगैरहा दिलवाकर थानो को मजबूत करवाएगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने पूछा तो कुछ नही है, केवल सुझाव अच्छे दिए है। इनकी बात सुझाव के आधार पर तो ठीक हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी

कोि ा ा है कि सारे बौर्डर पर कंट्रोल किया जाए, इसलिए हमने थानो मे जिप्सियां भी दी है और पूरानी हथियारो को बदला भी है। पिछले महीने ही हमने 30 जिप्सिया दी है। साथ ही हमनु पुलिस स्टे ान की तादाद भी बढायी है ताकि बौडर मजबूत हो सके और पजाब की तरफ से इधर उग्रवादी न आ सके या यू0पी0 की तरफ से भी इस तरह की कोई अन्य वारदात न हो सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सोचती है। अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो हमारी सरकार ने फौरन ही अपराधियो को पकडा है और पकडती है। अध्यक्ष महोदय, आप देखगे कि हरियाणा मे अन्य दूसरे स्टेटस के मुकाबले मे इस तरह के क्राईम बहुत ही कम है।

डा0 राम प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, दे ा मे बहुत ही कम अपराधियो को आज तक सजा मिल पायी हैं। इस नाते मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या उनके नोटिस मे भौखडी गांव की घटना है? यह गांव रादौर के पास है, उस गांव मे एक हरिजन नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। बलात्कार करने वाला अपराधाी की बेल नही हो सकती पर इस केस मे जमानत भी हो गयी। बलात्कार के केस मे उनको जमानत पर नही छोडा जाना चाहिए या लेकिन चाहिए था लेकिन उनको इसलिए छोड दिया गया ताकि वह अन्यत्र विवाह कर सके। अध्यक्ष महोदय, इस घटना को लेकन वहा पर बहुत जन आक्रोस है।

श्री अध्यक्षः यह तो अलग क्वै चन है।

डा0 राम प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, मै भौखडी गांव के केस की बात कर रहा हू। अपराधा करने वाले अपराधी को विवाह के लिए छोड दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से जमानत पर अपराधियो को छोडते चले गए, फिर तो कोई भी अपराध सजा प्राप्त कर ही नही पाएगा?

श्री अध्यक्षः राज प्रका ा जी, जमानत तो कोर्ट करता है।

डा0 राम प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है, जमानत तो कोर्ट ही करता है लेकिन जो सरकारी पक्ष है, जिसने केस दायरा किया है, उनका वकील भी तो अपनी बात कहने के लिए वहा पर जाता हो होगा। वकील तो पे ा हुआ ही होगा, फिर क्यो नही उनके वकील ने इस बात डिफैड किया? इस तरह से तो अपराधी मिल मिलकार अपना काम करते ही रहेगे और उनके केस को कुछ भी नही होगा और समय के साथ साथ उनके केस का कुछ भी नही होता। अपराधी बिना सजा प्राप्त किए हुए ही रहे जाते है जैसे भूतमाजरा वाले केस मे हुआ है। वह केस आज तक भी ऐसे ही पडा हुआ है और उसका कोई भी फेसला नही हुआ है।

श्री अध्यक्षः आपकी सप्लीमैट्री मेन क्वै चन से रिलेटिड नही है। इसलिए आप बैठ जांए।

Setting up of 132 K.V Power Station at Munak

***711 Shri Kirshan Lal:** Will the Minister for power be pleased to state whether there is any propsal under consideration of the Govt. for setting up at 132 K.V Power Station at Village Munak in Distt Karnal during the year 1993-94?

Power Minister (Shri A.C Chaudhary): No, Sir

श्री कृश्ण लालः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि मुनक मे जिस 132 के0वी0 पावर स्टे ान बनाने का निर्णय पिछली सरकार ने लिया था और जिस पर कि पिछली कई साल से मैटीरियल भी पडा हुआ था, अब यह मैटीरियल वहा से हटा दिया गया है। क्या सरकार इस पावर स्टे ान को बनाएगी, साथ ही इस मैटीरियल को वहा से हटाने के क्या कारण है?

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, मेरे भाई ने यह निराधार बात कर दी कि सामान उठ गया। वास्तव मे ये अगर अपना क्वै चन देखे तो उसका ही मैने सीधा सा जवाब दिया था। जहा तक स्कीम का ताल्लुक है, वह आलरेडी इन हैड है। इस पर पांच करोड की इन्वैस्टमैट होनी हैं। इसलिए मै उम्मीद करूगा कि आने वाले कुछ महीनो मे इसकी अच्छी खासी रिपोर्ट मिल जाएगी लेकिन इसकी कपली ान दो साल तक संभव है।

Leakage of Pipes

***731 Smt. Shandrvati:** Will the Minister for Public health be pleased to state-

(a) whether any complaint of mixing of drinking water with the sewerage water in the State has been reveived during the current yera; and

(b) if so, the details thereof; togetherwith the steps taken or proposed to be taken to prevent such occurrence in future?

जन स्वास्थय मंत्री श्री राम पाल सिंह कंवरः

(क) जी हां।

(ख) जन स्वास्थय विभाग ने भाहरो की जलवितरण एवम मल निकास के रख रखाव का कार्य 2.4.93 से अपने हाथ मे लिया। इसके तुरन्त प चात सभी भाहरो मे ये सर्वेक्षण कराया गया कि जो त्रुटिपूर्ण निजी पानी के कनैक ान नालियो व मेहनत से गुजरते है और स्वच्छ पानी को दूशित करने का कारण बनते है उनका पता लगाया जा सके । जो ऐसे सभी त्रुटीपूर्ण कनैक ान पाये गये उनको ठीक कर दिया गया। वि ोशकर ि ाकायते गन्दे पानी के बारे मे बहादुगढ, भिवानी, रोहतक और गुडगांव से प्राप्त हुई है और उनको ठीक करने की कार्यवाही भीघ्र कर ली गई। इस मामले मे सर्तक सावधानी प्रयोग की जा रही है। और ज्यो ही कोई त्रुटिपूर्ण पानी का कनैक ान पता लगता है उसको बिना किसी विलम्ब के ठीक करवा दिया जाएगा।

इसकी रोकथाम के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे है–

1. रिसाव कर रही जल वितरण पाईपो को भीघ्र ही ठीक किया जाता है। ताकि गन्दे पानी के बाहरो प्रवे ा से कोई प्रदुशण न हो।

2. जल वितरण व्यवस्था को पूर्णतया क्लोरिनेटिड किया जाता है और यह नि चत रूप से जांच लिया जाता है कि जल वितरण प्रणाली मे डाली गई क्लोरीन मांत्रा बाछनीय है।

3. जैसा कि यह देखा गया है पानी का दूशित होने का कारण पुरानी जग लगी हुई है जी0आई0पाईप है जो निजी पानी के कनैक ानो मे प्रयोग हुई है। सभी पुरानी जल वितरण पाईप कनैक ानो का पता लगाने व उनके बदलने का धमाके पूर्ण अभियान भीघ्र ही भाुरू किया जा रहा है। ताकि यह पता लगे सके कि दूशित पानी कहा कहा है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, इस प्रकार की गल्तिया जहा जहा पर है ये क्रिमिनल नैगलीजैसी मे आती है। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूगी कि जिन्होने ये गल्तिया की है, क्या उसको जिम्मेदारी ठहराया गया है, यदि ठहराया गया है तो उनको क्या सजा दी गई है और सरकार इसको फुलप्रुफ बनाने के लिए क्या स्टैप ले रही है?

श्री राम पाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, ज्यो ही हमारे नोटिस से यह बात आई हमने अपने डिपार्टमैट के थ्रू पता करवाया। जहा पर भी इस प्रकार के प्राईवेट कनैक ान और नालिया गली हुई मिली है, उसके मालिको को तुरन्त हुक्म दिया कि इनको बदलवा ले क्याकि प्राईवेट कनैक ानो का पाईप कज्युमर सप्लाई करता है।

श्रीमती चन्द्रावतीः जनाब, मेरा सवाल यह था कि जिन्होने क्रिमिनल नैगलजैसी की है क्या उनको जिम्मेदार ठहराया है और यदि गल्ती पाई गई है तो उनको क्या सजा मिली है?

श्री रामपाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, जैसे मैने बताया है कि यह काम पहले म्यूनिसिपल कमेटी के पास था। 2.4.1993 से हमारे महकमे के पास आया है। उसके प चात तुरन्त ही हमने युद्धस्तर पर प्रयास किया है। महकमे के औफिसरो को हुक्म दिया कि जहां भी प्राईवेट कनैक ान की पाईप गल गई है, उसके कज्यूमर्ज को तुरन्त नोटिस दे कि वे उन्हे बदलवाए। जहा इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण पाइपे थी, उनको फौरन ही ठीक करवाया है। इसके अलावा कुछ ि ाकायते के माध्यम से भी हमे पता लगा है। कुछ त्रुटिपूर्ण पाईप जो पाईपो के ऊपर से गई है, उनका तुरन्त ही पता लगा लिया है और उनको तुरन्त ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा, जो अन्डर ग्राउन्ड पाईप्स है, उनके बारे मे भी पता किया जा रहा है कि कहा कहा लीकेज है।

श्रीमती चन्द्रावतीः सर, मै जो जिम्मेवार की बात पूछ रही हू और मंत्री महोदय दूसरा ही जवाब दे रहे है। मै यह पूछना चाहती हू कि जिस अफसर की जिम्मेवारी थी और जिसने यह क्रिमीनल एक्ट किया है, उसके खिलाफ नैगलीजैसी के लिए क्या ऐक ान लिया है। जिस किसी अधिकारी का यह क्रिमीनल एक्ट आफ नैगलीजैसी है उसके लिए उसको क्या सजा दी है?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसे ही कह रही है। यह तो यह नाम बताये कि इस जगह पर गबडड है। (व्यवाधान एवम भाोर) जहां तक सीवरेज लगाने का सवाल है या पीने का पानी देने का सवाल है, पहले यह काम म्यूनिस्पिल कमेटीज के एरिया मे म्यूनिसिपल कमेटी किया करती थी। आज से कोई 20,20,25 या 30 साल पहले की पाईप लाईन हैं आपको पता है कि जब इतनी ज्यादा पुरानी पाईप हो जाती है तो कही न कही से लोकेज तो हो जाती है आज यहा पर खडे होकर कहना बडा ही मु कल है कि इसके लिये किस अधिकारी का कसूर है। हो सकता है वह अधिकारी मर चुका हो या रिटायर भी हो चुका हो। बात तो यह है कि कही पर ताजा पाईप डाली हो और उसमे लीकेज हो रही हो, तब तो हम ऐक ान लेगे लेकिन जहां कही पर पुरानी पाईप्स लगी हुई है और वे, अब ठीक नही है, सीपेज होने की वजह से या किसी दूसरी वजह से पक्चंर हो गयी है तो उनको जल्दी से जल्दी हम ठीक करने की कोि ा ा करेगे।

ताराकित प्र ान सख्या 733

यह प्र ान पूछा नही गया क्यो कि इस समय माननीय सदस्य श्री अमर सिह ढाडे सदन मे उपस्थित नही थे।

Manually Carrying of Human Excreta

*** 803 Dr. Ram Parkash:** Will the Minister of State for Welfare of Scheduled Castes and Back Ward Classes pleased to state the district wise number of families who maunally carry human excreta in the State togheter with the steps taken or proposed to be taken in to abolish this bad custom?

अनुसूचित जातिया एवम पिछडें वर्ग कल्याण राज्य मंत्री चौधरी जोगिन्द्र सिंहः श्रीमानी जी विवरण विधान सभा पटल पर रखा है।

विवरण

सिर पर मैला उठाने वाले परिवारो की वर्श 1992–93 के दौरान जिलावार संख्या निम्न अनुसार हैः–

क्रमसख्या	जिला	परिवारो की सख्या
1.	पानीपत	144
2.	करनाल	466

3.	सोनीपत	225
4.	जीन्द	419
5.	फरीदाबाद	727
6.	कैथल	724
7.	कुरूक्षेत्र	531
8.	अम्बाला	861
9.	सिरसा	113
10.	महेन्द्रगढ	255
11.	रिवाडी	488
12.	यमुनानगर	730
13.	भिवानी	654
14.	हिसार	547
15.	गुडगाव	527
16.	रोहतक	360
	कुल	7771

इस प्रथा को समाप्त करने हेतू राज्य सरकार एक केन्द्रीय प्रयोति स्कीमे ''मेहतरो तथा उनके अश्रितो की मुक्ति तथा पुनर्वास'' परिपालित रही है। इस स्कीम के अन्तगर्त मेहतरो तथा उनके आश्रितो को सम्मान जनक ंधधो मे पुनर्वासित करने हेतु वित्तीय सहायता तथा प्र ाक्षण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भुशक भाौचालयो को जलायुक्त भाोचालयो मे परिवर्तित किया जा रहा है।

डा0 राम प्रका ा: स्पीकर साहब, मै यह जानना चाहता हू इस कुप्रथा को कब तक समाप्त किया जा सकेगा? एक बात मै कहना चाहता हू । मंत्री महोदय ने जो सर्वेग करवाया है यह जानने के लिए यह मैला ढोने का गन्दा काम अब तक कितने आदमी कर रहे है? उस सर्वे के आकडो से सफाई कर्मचारी सतुश्ट नही है। समाचार पत्रो मे तो ऐसा भी छपा था कि इस वर्ग से सम्बन्धित निर्वाचित विधान सभा सदस्य भी इससे सतुश्ट नही है। क्या मंत्री महोदय, इस बारे मे दोबारा कोई सर्वे करवायेगे? तीसरी बात जो आपने कही है कि ड्राई लैट्रीन्ज को फल ा लैट्रीन्ज मे कन्वर्ट करने की कोि ा ा की जा रही है, यह अच्छी बात है। इस स्कीम का जो लाभ पहुचना चाहिए था, वह उन तक नही पहुचा है। बहुत से लोगो ने इसके लिए जो दिवारे बनानी थी, वह नही बनाई है क्यो कि वह बनाने के काबिल नही है। इसलिए यह स्कीम पूरी नही हुई है। क्या सरकार इस स्कीम को अनूसूचित जाति एवम पिछडा वर्ग कल्याण विभाग को सौपने पर विचार करेगी?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जो सिर पर मैला ढोने की प्रथा है, वह वाकई समाज के माथे पर बडा भारी कलंक है। इसी बात को लेकर हमने फल ा भाोचालय की स्कीम चलायी है। हमारी यह पूरी कोि ा ा होगी की आठवी पचवर्शीय योजना के अन्त तक इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाये। ऐसी हमारी स्कीम है। हमने इसके लिए कुछ कदम भी उठाये है। हम इस दि ाा मे बडी तेजी से आगे बढ रहे है ताकि इस प्रथा को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाये।

डा0 राम प्रका ा: सर्वे के बारे मे भी बताये।

चौधरी जोगेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, बात ऐसे है कि सी0एम0 साहब ने एक मीटिग कर के इस बारे मे सैट्रल गवर्नमैट को एक लैटर 4.2.1991 को लिखा है कि उनको ट्रेनिग देते समय जो 150 रूपये स्टाईपैन्ड का दिया जाता है, यह बहुत ही कम है। इसमे कोई भी आदमी जो इस काम को छोडकर दूसरे कार्य की ट्रेनिग लेगा, अपने बाल बच्चे पाल नही सकता। इस लिए हम ने उनसे मांग की है कि यह स्टाईपैन्ड को ज्यादा दिया जाये इसके अलावा सर्वे किये गए परिवारो के बच्चो मे से लेडीज को हम आई0टी0आईज0 मे भी कटिग ओर टेलरिग की ट्रैनिग दिलवाते है। दूसरे मैग्बर्ज को दूसरी ट्रेनिग दिलवाते है। एक दिक्कत और आती है कि हम तो कई बार उनके लिए कुनबे मे से किसी से पहले तो लोन नही ले रखा है अगर उसके कुनबे मे से किसी ने भी लोन लिया हुआ हो तो वह उसको दोबारा लोन नही देते। से

कमजोर लोग है इसलिए इनकी आर्थिक हालत सुधारनी पडेगी। इनकी हालत सुधारने के लिए मेहतरो तथा उनके आश्रितो को विभिन्न आय उपार्जन योजना के अन्तर्गत अनुदान, सीमान्त धन तथा बैक ऋण के रूप मे 500000.00 रूपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसमे कुल योजना लागत पाचस प्रति ात अनुदान के रूप मे। अनुदंान की अधिकतम सीमा दस हजार रूपए, पन्द्रह प्रति ात सीमान्त धन के रूप मे निगम द्धारा व भोश रा ि ा बैक ऋण के रूप मे उपलब्ध करवाई जाती है। इन को बैको से कर्जा लेने मे काफी कठिनाई आती हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लैटर भी लिखा है।

श्री अध्यक्षः स्आईपैड क्या है?

चौधरी जोगेन्द्र सिंहः एक सौ पचास रूपए वजीफे के तौर पर ट्रेनिग लेने वाले को दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः ट्रेनिग आप किस चीज की देते है?

चौधरी जोगेन्द्र सिहः महिला मेहतरो तथा उनके आश्रितो को सिलाई तथा कटाई मे 6 मास का प्र ि ाक्षण दिया जाता है। मेहतर तथा उनके आश्रितो को आव यक प्र ि ाक्षण ट्राइसेम स्कीम के अन्तर्गत निजी दुकानो तथा वर्क ााप से भी दिलाया जा रहा है।

Mr. Speaker: Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Malekan Minor

*** 749. Shri Mani Ram Keharwala:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the consturction work of Mallekan Minor in District Sirsa has been supped; if so, the reasons thereof togethewith total amount incurred thereon so for, and

(b) whether there is any proposal under construction of Govt. to restart the construction work on the said minor?

सिचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा):

(क) हां मल्लेका माईनर का निर्माण कार्य आर0डी0 60000 से आगे रोक दिया गया था क्याकि आर0डी0 33900 से आगे कच्ची नहर जो कि रेतीले, ऊचे नीचे तथा ऊंचे टिब्बो मे से गुजरती है, मै पानी पहुच नही पारया इस के अतिरिक्त नहरी पानी की पूर्ती भी पर्याप्त नही थी, जो कि बारूवाली माइनर का इस समय की जा रही लाईनिग का कार्य प्रगति पर है के पूर्ण होने पर सीपेज एवम अवजोरप ान से होने वाली हानियां से बचाकर उपलब्ध हो सकेगी इस नहर पर अब तक 39.57 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की जा चुक है तथा

(ख) हां बारूवाली वित्रिका की लाईनिंग, पूर्व निर्मित मल्लेका माईनर की लाईनिंग पूर्ण होने तथा साथ ही पर्याप्त धन रा ि ा की उपलब्धि पर।

Vacant Posts of English Teachers

***828 Shri Ram Kumar Katwal:** Will the Minister for Education be pleased to state the number of schools; if any, in which English Teachers have not been posted in the State?

ि ाक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): ''नही'' राजकीय विधालयो मे इगलि ा आध्यपक का कोई पद नही है।

अतारिकत प्र न एवम उतर

Samples of Petsicides/Fertilizer

***174 Chaudhri Balwant Singh Maina:** Will the Minister for Agriclture be pleased to state-

(a) whether any permission is required by the manufacturers of other States to sell their Pesticides/Fertilizer in the Haryana State;

(b) if so, the names of the macufacturers to whom permission has been granted during the last five years and the criteria adopted therefor;

(c) the manufacturers wise number of samples of Fertilizers/Pesticides; if any taken during the period maontiaoned in part (b) above; and

(d) whether the samples out of those referred to in part (c) above were found snb standard, if so, the names of the manufacturers whose samples were fund sub standard and the action taken against them?

कृशि मंत्री (श्री हरपाल सिंह):

(क) हां । खादो के मामलो मे केवल सिंगल सुपर फसफेट तथा जिक सल्फेट के लिए अनुमति की आव यकता है।

(ख),(ग) कीटाना ाी दवाइयो तथा खादो के निर्माताओ के सम्बध मे सूचना क्रम ा तथा (घ) अनुबन्ध 1 तथा 2 मे दी गई है। कीटना ाी दवाईयो तथा खदो की बिक्री की आज्ञा प्रदान करते समय उनकी गुणवत्ता का मापदण्ड ध्यान मे रखा जाता है। ऐसा राज्य मे किसानो को अच्छी गुणवता की सामग्रियां सप्लाई सुनि ित करने के लिए किया जाता है।

Annexure-1

List fo the manufacturers who were granted permission for the sale of their pesticides in Haryana State.

Sr. No.	Name of the Manufacturer	Validity
1.	M/S Bharat Pesticides Manufacturing Company	”
2.	M/s Lupia Agri Chemicals (India) Ltd.	”
3.	M/s Punjab Saltpetre Refinery.	”

4.	M/s J& K Pesticides and Chemicals Corporation	”
5.	M/s Chemet Chemicals Pvt Ltd.	4-9-93
6.	M/s J.U Pesticides and Chemicals Pvt. Ltd	4-9-1993
7.	Indichem.	”
8.	Tropical Agrosystems Ltd.	”
9.	jay Dee Associates pvt Ltd	”
10.	Jay Dee Chemicals.	”
11.	M/s Unique Farmaid PVT Ltd.	”
12	Pesto Chem India	”
13	M/s Pesticides Indisa Ltd.	”
14.	Konkan Pesticides	”
15.	M/s National Organic Chemical Industries Ltd.	”
16.	M/s Gayatri Pestichem.	”
17.	M/s All India Medical Corporation.	”
18.	M/s Gujrat Krishi Chem. Corporation.	”
19.	M/s Ghards Chemicals Ltd.	”
20.	M/s Enzymes Pharmaceticlas and Indl.	”

	Chemical Pvt. Ltd.	
21.	M/s E.I.D Parry India Pvt	”
22.	Bhavani Fertilizers Regd.	”
23.	M/s M/s Chopal Pesticides.	”
24.	M/s Sandoz India Pvt	”
25.	M/s Evergreen Pesticides	”
26.	Trillo Industrices Pvt Ltd	”
27.	M/s Coromandel Indag Products India Pvt	”
28.	M/s Agrimas Chemicals Pvt. ltd.	”
29.	M/s Food and Allied Products	”
30.	M/s Markfed Agro Chemicals	”
31.	M/s Gujrat Narmada Valley Fertlizers Company Ltd	”
32.	M/s Agro aids Pesticides	”
33.	M/s Searle India Ltd.	”
34.	M/s Ajay Ferti. Chem. (Bombay) Pvt. Ltd.	”
35.	M/s New Chemi Industries Ltd.	”
36.	M/s United Phosphorus Ltd.	”
37.	M/s Hindustan Indesticdes Ltd.	”

38.	M/s Evid and Company Chemicals Ltd.	4-9-1993
39.	M/s Hoechst India Ltd.	”
40.	M/s Khatau junker Ltd	”
41	M/s Shreeji Pesticides Pvt Ltd.	”
42.	M/s National Farm Chemicals	”
43.	M/s Rallis India Ltd.	”
44.	M/s Devidayal Sales Pvt. Ltd	”
45.	M/s Sulphur Mills Pvt. Ltd	”
46.	M/s Indian Pest Control Co.	”
47.	M/s Agromore Ltd	30-9-1993
48.	M/s Pest Control India Ltd.	”
49.	M/s Parkash Pulverising Mills	”
50.	M/s Monsanto Chemicals of Inida Ltd.	”
51.	M/s Inidan Manufacturing Co.	”
52.	M/s Bharat Pulveristing Mills Ltd.	”
53.	M/s Omega Agro Pvt. Ltd.	”
54.	M/s Punjab Pesticides Industrial Cooperative Society Ltd.	”
55.	M/s Crop Health Products Ltd.	”
56.	M/s Universal Agro Chemical Industries	”

	(P) Ltd.	
57.	M/s Indofil Chemicals Companyu	”
58.	M/s Bharati Minerals Pvt. Ltd	”
59.	M/s Gujrat Agro Industries Corp Ltd.	”
60.	M/s Suvochem Industries Pvt. ltd	”
61.	M/s Heema Pesticdes	”
62.	M/s Singhal Pesticides Industires.	”
63.	M/s J K M B Ltd.	”
64.	M/s Monrari Industries Ltd.	”
65.	M/s Kisan Chemicals.	”
66.	M/s Mascot Agro Chemicals	”
67.	M/s Inseetidides & allied Chemicals.	”
68.	M/s Solar Pesiicides Pvt. Ltd.	”
69.	M/s Universal Chemical Company.	”
70.	M/s Hindustan Pulversing Mills	”
71.	M/s Mysore Agro, Chemical Co. Pvt ltd	30-9-1993
72.	M/s Sumas Chemicals Ltd.	”
73.	M/s Atul Pesticices Pvt. Ltd	”
74.	M/s Unikill Pesticdes (P) Ltd.	”

75.	M/s Excell Industries Ltd.	”
76.	M/s Bayer India Ltd.	”
77.	M/s Atlay Laboratories Pvt. Ltd.	”
78.	M/s Avid Pharmaceulticals Pvt. Ltd.	”
79.	M/s Chith Chemicals.	”
80.	M/s Sudershan Chemical Ind. ltd	”
81.	M/s Kissan Agro. Chemicals.	”
82.	M/s Shivalik Agro Chemicals.	”
83.	M/s Hindustan Ciba Geigy Ltd.	”
84.	M/s Cynamid India Ltd.	”
85.	M/s Gupta Chemicals Pvt. Ltd.	”
86.	M/s Apex Minerals Pvt. Ltd.	”
87.	M/s Somanil Chemicals Co.	”
88.	M/s Agro Industrial Chemicals Co.	”
89.	M/s Chhatisgarh Pesiticides Pvt. Ltd.	”
90.	M/s Agro Chemicals.	”
91.	M/s Herbicides Inida Ltd.	”
92.	M/s Chemico Pesticides Combline	”
93.	M/s Hindustan Antibiotics Ltd.	”

94.	M/s Pestchem & Allied Industries	”
95.	M/s Shine Metal Industries.	”
96.	M/s Super Industries.	”
97	M/s Gautam Udyog.	”
98	M/s Ploneer Pesticldes Industries.	”
99.	M/s BASF India Ltd. Sasya Rakahana Industries.	”
100.	M/s Sasya Rakahana Industries.	”
101.	M/s Meerut Agro Chemical Industries.	30-9-1993
102.	M/s President industries.	”
103.	M/s Shiv Shakti Pipe Insustries.	”
104.	M/s Shaw Wellace and Co.Ltd.	”
105.	M/s Goenka Industries.	”
106.	M/s Cashew Agri Chemleals Pvt. Ltd.	”
107.	M/s Agro Chemicals Industries.	”
108.	M/s United Pesicides.	”
109.	M/s Sunbeem Agro Chemicals Punjab Ltd.	”
110.	M/s ICI India Ltd.	”
111.	M/s Asr Cee Crop Care Insecticldes Pvt. Ltd.	”

112.	M/s Union Pesticides Pvt. Ltd.	”
113.	M/s Ventech Pesticides Ltd.	”
114.	M/s Vallabh Pesticides Mfg. Co.	”
115.	M/s Bangalore Pesticides Ltd.	”
116.	M/s Hyderabad Chemical Supplies Ltd.	”
117.	M/s Sanwin Laboratiories.	”
118.	M/s Mahhu Sudhan Indusries	”
119.	M/s Bharat Pesticides Industries Pvt. Ltd.	”
120.	M/s Paryl Chemicals Pvt. Ltd.	”
121.	M/s K.P Industries.	”
122.	M/s Ahlawat Agro Chnmical.	”
123.	M/s Vajalnkshmi Insecticides & Pesticides Pvt. Ltd.	”
124.	M/s Imkemex India Ltd.	”
125.	M/s Moti Lal Pesticides Inida Pvt. Ltd.	”
126.	M/s Siris India Ltd.	”
127.	M/s HIM Chemical India.	”
128.	M/s Agarwal Industies.	”
129.	M/s Goel Agro Chemical Bombay.	”

130.	M/s Hindustan Chemical Industries.	”
131.	M/s Solar Barma Chemical Ltd.	”
132.	M/s Bhaskar Agro, Chemical Pvt. Ltd.	”
133.	M/s Tutlcorian Akali Chemical & Fertillzers Ltd.	”
134.	M/s Gujarat Pesticines.	”
135.	M/s Singhal Minerals Pvt. Ltd.	”
136.	M/s Patron Laboratories.	”
137.	M/s Raashi Fertllizers Ltd.	30-9-1993
138.	M/s T. Stanes and Co. Ltd.	”
139.	M/s Modern Insecticides Pvt. Ltd.	”
140.	M/s Goyal Chemical India	”
141.	M/s Voltas Ltd.	”
142.	M/s Insects Pesticides.	”
143.	M/s Agro. Chemical & DE Pest Corp.	”
144.	M/s Pioneer Products Ltd.	”
145.	M/s Pooja Minerals & Chemicals.	”
146.	M/s Paramount Pesticides.	”
147.	M/s Vithaj Agri. Chemicals.Industries Pvt. Ltd.	”

148.	M/s Singhal Pesticides Pvt. Ltd.	”
149.	M/s Standard Pesticides Pvt. Ltd.	”
150.	M/s Med. Chemicals.	”
151.	M/s New med. Chemicals.	”
152.	M/s Ganga Crop. Safc Pvt. Ltd.	”
153.	M/s Amba Chemical Industires.	”
154.	M/s Kanoria3 Chemicals & Industries Ltd.	”
155.	M/s Slipest Pvt. Ltd.	”
156.	M/s Vallabh Pesticides Pvt. Ltd.	”
157.	M/s Lupin Agro. Chemicals (India)Ltd.	21-12-1994
158.	M/s Montari Industries Ltd.	”
159.	M/s NOCIL	”
160.	M/s Pesto Chemical India.	”
161.	M/s Searle India Ltd.	”
162.	M/s Singhal Pesticides Industries.	”
163.	M/s Hoechest India Ltd.	”
164.	M/s Goel Agro. Chemical Bombay	30-4-1994
165.	M/s MARKFED Agro. Chemicals.	31-12-1994

166.	M/s Aar Cee Crop. Care Insecticides Pvt. Ltd.	”
167.	M/s Rollis India Ltd.	”
168.	M/s Unieue Farmaid Pvt. Ltd.	”
169.	M/s Bharat Pesticides Mfg. Co.	”
170.	M/s TCM & Co. Ltd.	26-9-1994

NAME OF THE MANUFACTURER TO WHOM PERMISSION IS GRANTED TO SELL THE FERTILIZERS IN THE STATE.

1989-90

Nil

1990-91:-

(i)	M/s Bharat Fertilizers Manufacturing Com.
(ii)	M/s Indo Plast Pvt. Ltd. Industrial Arca, Parwanoo (H.P)
(iii)	M/s isha Chemic Is Micro Nutrients Pvt. Ltd.
(iv)	M/s Charkradhar Chemicals Pvt. Ltd.
(v)	M/s Ram Ganga Fertilizers Ltd.

1991-92

1.	M/s isha Chemic Is Micro Nutrients Pvt. Ltd.
2.	M/s Rattan Micronutrients Pvt. Ltd.

3.	M/s Hind Chemicals & Fertilizers
4.	M/s Shivalik Chemicals Pvt. Ltd.
5.	M/s Puneet Chemicals and Mechanical Works.
6.	M/s Chemi Ferti.
7.	M/s Indo Plast Pvt. Ltd.
8.	M/s Randeep Paper Board Mills.
9.	M/s Pal Chemicals and Fertilizers
10.	M/s Jyoti Chemicals and Fertilizers
11.	M/s India Phosphate and Corbonate

1993-94

1.	M/s Defence Agro Chemicals & Fertilisers
2.	M/s Kailash Paints and Chemicals
3.	M/s Rattan Micro Nutrients Pvt. Ltd.
4.	M/s A.J Metals Pvt. Ltd.
5.	M/s Sona Fine Chem. Pvt. Ltd.
6.	M/s Jai Shree Agro Industries
7.	M/s Gee. Emm. Inteprises
8.	M/s Namdev Chemicals and Alled Industries
9.	M/s Isha Chemicals & Micro nutlents Pvt.

	Ltd.
10.	M/s Shivalik Chemicals Pvt. Ltd.
11.	M/s Pant Nagar Fertiliser Ltd.
12	M/s Gee Ess Chemiclas Fertilizers
13	M/s Indo Plast Pvt. Ltd.
14.	M/s Chemi Fert
15.	M/s Jindal Industries
16.	M/s Jyoti Chemicals & Fertilzers
17.	M/s Him Chemicals and Fertizers
18.	M/s Gandhi Chem. Ertilzers Industries
19.	M/s India Phosphate & Chemicals Manufacturing Co.
20.	M/s Rama Agro Industries
21.	M/s Randeep Papers Board Mills
22.	M/s Sardarh Chemi Fert Industries
23.	M/s Kay Chemicals Industries
24.	M/s Batar Chemi feri Pvt. Ltd.
25.	M/s Bharat Fertilizer manufacturings Co.
26.	M/s Varinder Agro Chemicals Ltd.
27.	M/s Munak Chemicals Ltd.

28.	M/s Khatan Fertilizers
29.	M/s Ram Ganga Fertilizers
30.	M/s Shree Acid and Chemicals
31.	M/s Shivalik Fertilizers
32.	M/s Rallies India Ltd.
33.	M/s Indo Feed Agencies Pvt. Ltd.
34.	M/s Libra Sales Pvt. Ltd.
35.	M/s Coromendal Fertilzers Ltd.
36.	M/s Mineral & Metal Trading Corporation of India

Sr.	Name of the manufacturer	Samples drawn					Sub Standard					Action Taken			
		89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	Licence cancelled	Prosecution Launched	Warning	Underprocess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Pesticides India	TOTAL SAMPLES DRWA	17	9	22	12	1	2	1	6	-	-	8	2	-

		N-1010													
2.	Vimal Pesticides		-	1	-	-	-	-	1	6	-	-	8	2	-
3.	Untied Pesticides		7	1	4	4	-	4	-	2	1	-	7	-	-
4.	Volats Ltd		1	1	-	5	-	-	1	-	2	-	1	-	2
5.	National Farm Chemicals		2	4	5	5	-	1	1	4	-	-	4	2	-
6.	Kishan Agro Chemicals		3	2	1	1	1	-	2	1	-	1	2	1	1
7.	Somnil Chemical		-	1	6	1	-	-	1	5	-	-	6	-	-
8.	Konkan Chemical		-	2	1	3	-	-	2	-	2	-	1	1	2
9.	Pioner Products		-	1	2	25	-	-	1	1	-	-	2	-	-

10.	Northern Minerals		77	79	59	21	1	3	4	17	1	-	24	1	1
11.	S.N. Chemical Industries		14	23	24	5	-	1	4	3	-	-	8	-	-
12	Crop Health Products		6	8	9	4	-	1	5	3	1	-	9	1	-
13	Unique Farm Aid Pvt. Ltd.		6	8	14	11	-	1	-	8	6	-	15	-	-
14.	Jai Shri Agro Industries		-	1	15	19	-	-	1	5	3	-	8	1	-
15.	Singhal Pesticides		4	1	11	7	-	-	-	6	-	-	5	1	-
16.	Pesto Chemical India		11	16	22	19	-	1	2	1	3	-	6	2	-
17.	Parkash		-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Puiverising Mils														
18.	Golden Chemicals	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
19.	India Manufactruing Co.		4	3	5	5	-	-	2	3	2	-	6	-	-
20.	Omega Agro Pvt. Ltd.		6	4	1	-	-	1	3	1	-	-	3	2	-
21.	Goenka Industries		1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Gayatri Krishi Chemicals		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Hyderabad Chemicals		2	2	2	10	-	1	1	-	-	-	1	1	-
24.	Crop Care		4	7	2	1	-	1	3	2	-	-	4	2	-

25.	Haryana Chemical & Pesticides		9	11	8	9	-	-	2	-	-	-	2	-	-
26.	Heema Pesticides		6	5	6	2	-	-	1	6	2	-	8	-	1
27.	Veema Chemicals		1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
28.	Untied Pesticides		-	4	7	4	-	-	3	-	1	-	4	-	-
29.	Gautam Udyog		-	4	5	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-
30.	Meerut Agro Chemicals		1	3	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
31.	Shivalik Agro Chemicals		4	4	7	4	-	4	1	-	2	-	5	2	-
32.	Shiv Shakti Pipe		7	3	8	-	-	5	3	5	-	-	11	2	-

	Industries														
33.	Gujrat Krishi Chemical Cropn.		6	2	5	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
34.	H.A and F.C		79	38	57	138	-	-	1	2	7	-	1	2	7
35.	Jai Chemicals		27	22	19	8	-	-	3	5	1	-	4	-	1
36.	Rajhans Chemicals		-	1	7	3	-	-	-	3	2	-	4	-	1
37.	Avid & Co. Ltd.		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	Sarle India Ltd		7	3	20	13	-	-	-	2	6	-	4	1	3
39.	Hindustari Ciba Giegy Ltd		10	14	18	11	-	-	1	2	-	-	1	1	-
40.	Gharda		4	1	1	15	-	1	-	2	3	-	1	1	2

	Chemiclas			0	6										
41	Hafod Pesticides		49	19	38	25	2	1	-	3	-	-	3	2	1
42.	Thakkar Chmicils		23	13	19	16	-	-	1	2	-	-	2	1	-
43.	Tropical Agro Systems		8	4	15	5	-	4	-	6	5	-	10	1	4
44.	Bharat Pesticide Mfg. Co.		-	11	16	14	-	-	3	11	1	-	13	-	2
45.	Hindustan Insecticides Ltd		6	8	3	8	-	-	1	1	-	-	1	-	1
46.	Tas Chemicals		7	6	1	1	-	1	3	1	1	-	5	-	1
47.	Gujra Stat Co. Marketing Fedration		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Limited														
48.	Kisan Chemicals Unit of Montari		1	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
49.	Cashew Agri Chemicals		3	5	3	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
50.	Green Gold		1	3	1	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-
51.	BASF Indis Limited		2	4	6	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
52.	Monsanto Chemical of India Ltd.		3	2	4	3	-	-	-	2	-	-	2	-	-
53.	Hoechest		9	14	23	12	-	-	1	-	1	-	1	-	1
54.	Excel Industries Ltd.		10	9	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

55.	All Indiax Medical Corpn.		1	2	6	1	-	-	1	6	1	-	6	1	1
56.	Kissan Chemicals		9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	United Phoshorus		4	21	11	17	-	-	3	3	3	2	5	-	2
58.	Madhusudhan Industries		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	Swastik Chemicals & Pesticides		22	15	17	19	-	2	7	4	5	1	11	1	5
60.	Agromore Limited		2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
61.	Sudershan Chemical Indust		10	3	6	14	-	4	-	3	5	-	7	-	5

62.	I.C.I		3	3	1	1	-	-	1	1	-	-	4	1	-
63.	Sulphar Mils Pvt Ltd		6	5	5	5	-	-	-	2	1	-	4	-	-
64.	E.I.D Parry Ltd.		3	1	4	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-
65.	Agro Chemical Industries		1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-
66.	Super Industries		1	3	3	1	-	1	2	2	1	-	4	-	2
67.	Sumex Chemical Ltd.		3	3	7	3	3	1	-	-	2	-	3	2	1
68.	Bayer India Ltd.		4	8	7	9	-	-	-	2	-	-	1	1	-
69.	NOCIL		41	21	39	18	-	1	-	8	1	-	6	3	1
70.	Jainsons Minerals		5	9	1	5	-	-	1	-	3	-	1	-	3

71.	Shakit Insecticides Ind.		-	5	4	8	-	-	2	3	2	-	5	-	2
72.	H.P.M		28	22	37	20	-	-	7	17	1	-	21	-	3
73.	Plant Care Concertrates		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
74.	Goyal Argo Industries		6	6	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
75.	Neelam Agro Industries		6	8	2	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-
76.	Shaw Wallaces Co.		3	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-
77.	Markfed Agro Chemical		1	2	5	2	-	1	1	2	-	-	2	2	-
78.	Rallies India Ltd		2	2	1	14	-	-	-	-	1	-	1	-	-

			8	6	6										
79.	Solar Pesticides Pvt. Ltd.		-	1	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1
80.	Atul Pesticides Ltd.		-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.	Kamdhanu Pesticdes		-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-
82.	Sain Vin Lab.		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
83.	Agrimas Chem. Pvt. Ltd.		-	1	2	4	-	-	1	-	4	-	2	-	-
84.	Shri India Limited		3	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
85.	New Chem. Industries		6	8	10	10	-	2	3	3	6	-	11	-	-
86.	Montari		2	1	4	24	3	1	-	-	-	-	2	2	-

	Industries Ltd.		7	9	2										
87.	Indian Pest Control		1	2	3	-	-	-	2	3	-	-	3	-	3
88.	Mascor Agro Chemical		8	2	5	-	1	1	2	3	-	-	6	1	-
89.	Gurjat Narmada Vally Fertilizer Ltd.		4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
90.	Evid Co. Chemical		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.	Gujar Agro Ltd.		12	11	8	2	-	1	2	3	-	-	4	2	-
92.	Lupin Agro Chem.		11	9	8	9	-	1	1	1	-	-	2	1	-
93.	Gupta Chem.		5	7	3	4	-	1	5	1	-	-	6	-	1

	PVT. Ltd.														
94.	Indofit Chem. Ltd.		1	5	8	6	-	1	5	8	3	-	11	3	3
95.	Cyamid India Ltd.		6	7	12	3	-	1	2	1	-	-	3	1	-
96.	Bharti Minerals		6	7	7	9	-	1	3	4	3	2	8	1	-
97	Coromandal Indag India		4	2	7	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-
98	Jyoti Insecticides		5	5	7	4	-	2	1	5	1	1	8	-	-
99.	B.P.M		11	2	5	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-
100.	Shakti Insecticides		-	5	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
101.	Hindustan		-	3	1	1	1	-	3	1	-	-	4	1	-

	Chemical Industires														
102.	Bombay Pesticides & Insecticides		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
103.	B.L: Chemical		13	4	-	3	-	5	4	-	2	-	9	-	2
104.	Punjab Pesticides & Industrial Coop. Society		1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
105.	Herbicides India		4	3	6	3	-	1	1	2	1	-	3	2	-
106.	Agro Chemicals		2	3	6	3	-	1	1	2	1	-	3	2	-
107.	Agro Aids Pessicides		1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

108.	Subbeam Agro Chemicals		3	1	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-	-
109.	Insecticides & Allied Chemicals		3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
110.	Atlay Lab. Pvt. Ltd.		2	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1
111.	M.L. Industries		-	1	-	-	-	--	1	-	-	-	1	-	-
112.	Sandoz India Ltd.		8	3	3	4	-	1	-	-	1	-	-	1	1
113.	Avid & Co.	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
114.	Evid Pharmaceutical PVT. Ltd.		4	1	5	4	-	-	-	2	-	-	1	-	-
115.	Bhaskar Agro Chemicals		1	1	2	-	-	1	1	2	-	-	3	1	-

116.	B.L. Industries, Ellaenabad		5	7	1	-	-	2	4	1	-	-	7	-	-
117.	Khataj Junkar Ltd.		1	3	5	-	-	1	-	-	-	-	-	--	-
118.	Agro Industrial Corp.		-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	3-	-	-
119.	Ajay Fertilizers Chemicals		2	-	2	1	-	1	-	2	1	-	3	-	1
120.	Ambachem Industries		1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
121.	Anu Pesticides		-	-	2	16	-	-	-	1	-	-	1	-	-
122.	Aar Cee Crop Care		-	-	2	6	-	-	-	2	1	-	2	-	1
123.	Bhwagwati Minerals		-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

124.	Bharat Insecticides		5	-	9	-	1	-	-	4	-	-	3	1	1
125.	Bhopap Pesticides		-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126.	Bangaloren Pesticides		2	-	3	3	-	1	-	2	2	-	3	-	2
127.	Bharat Rasayan Ltd.		-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
128.	Delta Chemical Industries.		-	-	5	7	-	-	-	2	2	-	4	-	-
129.	Devi Dayal Agro Chem.		-	-	2	2	1	2	1	2	-	-	6	-	-
130.	Evergreen Industries.		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
131.	Gayatri		-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pesticides														
132.	Gujarat Pesiticides		-	-	4	1	-	-	-	3	1	-	3	-	1
133.	Growell Agor Products		-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134.	Dhanuka Pesticides		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135.	Growell Agro Chem. Bombay		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
136.	Gujrat Agro Chem.		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
137.	Southern Peto Chem		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
138.	Sandar Mfg. Co.		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139.	T.S Farms &		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Chem.														
140.	United India Pesticides		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
141.	United Pesticides.		-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	1	2	-
142.	Tuticon Akali Chem.		-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
143.	Siris Chem.		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144.	Shiphon chemicals		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
145.	Vam teca Pesticides		-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1
146.	Vijay Laxmi Pesticides		-	-	-	5	-	-	-	-	3	-	1	-	2
147.	Haryana		3	-	3	10	-	1	-	3	7	-	10	1	1

	Pesticides														
148.	Imkemex Industries		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
149.	Solar Pesticides		-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.	Indochem		-	1	-	6	-	-	-	1	4	-	3	-	2
151.	Jyoti Pesticides		-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
152.	Jayco Chemicals		-	-	1	11	-	-	-	1	1	-	2	-	-
153.	J.U.P Pesticides		-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
154.	J.K.B.M		1	-	3	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
155.	Unikill Pesticides		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
156.	Union Pesticides		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
157.	Montari		-	-	4	3	2	1	-	-	1	-	1	2	1

	Industries				2										
158.	Moti Lal Pesticides		-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	2	-	-
159.	Khandosh		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
160.	S.L. Allied Industries		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.	Khaitan		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.	P.C.M & Co.		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163.	Rohana Polymer		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164.	Bator India		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165.	J & K Pesticides		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
166.	Jay Dee Asociates		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

167.	Parkash Pulverising Mills		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168.	President Indsutries		-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
169.	Paushak		-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
170.	Parkh Enierprises		1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
171.	Parul Chemicals		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.	Camphor & Allied		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.	Goel Chemicals		1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
174.	Universla Chemico		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175.	Pesticides Allied Industries		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-

176.	Trilo Agro Industries		2	-	6	26	-	1	-	4	20	-	24	1	-
177.	Hindustan Laboratories		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178.	Sasya Rakshan Ltd.		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
179.	Tinal Agro Chem		-	-	2	-	-	-	-	1-	-	-	1	-	-
180.	Universal Agro Chem.		-	-	3	1	-	-	-	3	-	-	2	1	-
181.	Vallabh Pesticides		-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.	Duzon Agro Chemicals		3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
183.	Sunray		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184.	Petro Chem.		1	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-

185.	Kishan Pesticides		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186.	Arti Minerals		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.	Kissan Chem. Mfg.		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Manufacturer	Product	Drawn							
		1989-90	1990-91	91-92	92-93	93-94	89-90		
							R	T	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N.F.L	Urea	Na	Na	335	200	195	1	1	2
KRIBHCO	-do-	Na	Na	93	134	67	19	-	19
IFFCO	-do-	Na	Na	82	138	76	7	-	7
POOL	-do-	Na	Na	Na	Na	Na	4	-	4
UNKNOWN	-do-	Na	Na	8	13	7	11	-	11
I..P.L	-do-	Na	Na	9	34	60	-	-	-
SHRIRAM	-do-	Na	Na	85	72	23	-	-	-
CHAMBAL	-do-	Na	Na	21	24	4	-	-	-

GNFC	-do-	Na	Na	50	58	43	-	-	-
SHAKTIMAN	-do-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-
SPIC	DAP	Na	Na	200	168	144	-	1	1
PPL	-do-	Na	Na	337	275	75	-	1	1
KRIBHCO	-do-	Na	Na	52	22	13	1	1	2
IFFCO	-do-	Na	Na	109	196	110	2	1	3
UOKNOWN	-do-	Na	Na	7	6	3	5	-	5
POOL	-do-	Na	Na	Na	Na	Na	1	-	-
GNFC	-do-	Na	Na	Na	1	Na	-	-	-

Sub Standard												Action Taken					
1990-91	91-	92-	93-									FIR	Pros.	Warning	PRC	Sales stoppe	Under Proces

	92	93	94													d	s
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
R O T R O T R O T R O T																	
2	-	2	-	-	-	5	-	4	1	1	2	-	-	2	-	-	-
10	-	10	20	-	20	13	-	11	19	-	19	-	-	-	-	-	-
6	-	6	2	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	11	6	-	6	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-
2	-	2	3	8	11	-	2	-	5	2	7	4	-	1	-	7	1
-	-	-	9	-	9	2	3	5	2	-	2	1	-	-	-	-	2
6	-	6	-	1	1	3	1	4	3	1	4	1	1	2	-	-	-
13	-	13	5	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.P.L	DAP	Na	Na	65	56	17	-	-	-	-	-	-
PACL	-do-	Na	Na	79	42	14	-	-	-	-	-	-

CHAMBAL	-do-	Na	Na	Na	Na	117	-	-	-	-	-	-
HAFED	-do-	Na	Na	Na	Na	226	-	-	-	-	-	-
GSFC	-do-	Na	Na	78	52	91	-	-	-	-	-	-
IFFCO	NPK	Na	Na	30	59	22	13	-	13	5	-	5
HAFED	-do-	Na	Na	Na	3	NA	4	-	4	11	-	11
UNKNOWN	-do-	Na	Na	11	14	6	13	-	13	29	-	29
HF & C	-do-	Na	Na	24	30	21	-	-	-	-	-	-
JAI BHARAT	-do-	Na	Na	3	-	-	-	-	-	-	-	-
N.E.L	CA N	Na	Na	43	26	6	16	1	17	28	-	28
BHARAT												
CHEMICALS	SSP	Na	Na	Na	6	1	-	5	5	-	-	-
SHRI ACID	-do-	Na	Na	Na	3	6	-	1	1	-	-	-

RAM GANGA	-do-	Na	Na	Na	Na	6	1	1	1	-	-	-
UNKNOWN	-do-	Na	Na	Na	2	1	2	-	2	1	-	1
H.C.L	do	Na	Na	1	Na	3	-	-	-	2	-	2
HAFED	do	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	1	1
NITIN	do	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	-	-

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	-	1	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-

-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	10	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-
-	2	2	-	10	10	10	-	6	3	2	7	5	-	1
4	-	4	5	-	5	-	3	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	-	-	-	1
-	-	-	-	3	3	-	4	4	1	3	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

M/s												
ORINENTAL	SSP	NA	NA	103	107	63	-	-	-	-	-	-
CARBON												
AGRO CHEM	”	NA	NA	NA	4	NA	-	-	-	-	-	-
INDIA GERIOL	”	NA	NA	78	103	27	-	-	-	-	-	-
SHIVALIK	”	NA	NA	NA	5	1	-	-	-	-	-	-
MUNAK	”	NA	NA	NA	4	NA	-	-	-	-	-	-
BHARAT CHEM	”	NA	NA	NA	5	10	-	-	-	-	-	-
RAMPUR DISTIL	”	NA	NA	64	39	23	-	-	-	-	-	-
JAI SHREE	”	NA	NA	37	37	4	2	-	2	1	-	1

I.P.L	MOP	NA	NA					-	1	1	-	-
TATA	ZINE	NA	NA	NA	NA	NA	-	2	2	-	-	-
MAHESH	”	NA	NA	8	1	22	-	2	2	-	-	-
TRISHUL	”	NA	NA	NA	NA	NA	-	2	2	-	-	-
INDORPLAST	”	NA	NA	8	1	22	-	2	2	-	-	-
GANDHI CHEM	”	NA	NA	1	-	7	7	-	7	2	-	2
UNKNOWN	”	NA	NA	2	1	1	-	-	-	-	2	2
HARYANA	”	NA	NA	NA	9	11	-	-	-	-	1	1
AGROCHEM												
PRABHAT	”	NA	NA	NA	30	39	-	-	-	-	1	1
B.B CHEMICALS	”	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	1	1

VIKAS	”	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	1	1
KAILASH PAINTS	”	NA	NA	7	4	3	-	-	-	1	-	1
JINDAL	”	NA	NA	6	3	2	-	-	-	-	2	2

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	1	1	-	8	8	-	15	15	1	13	7	1	-	2
-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	1	3	4	-	1	1	-	1	2	-	-	1
-	-	-	3	3	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	2	2	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M/s												
JAI SHREE	ZINC	NA	NA	NA	9	11	-	-	-	-	-	-
HARYANA ZINC	”	NA	NA	NA	1	NA	-	-	-	-	-	-
UTTAR BHARAT	”	NA	NA	1	7	NA	-	-	-	-	-	-
SONIA OVERSEAS	”	NA	NA	-	9	14	-	-	-	-	-	-
PARKASH	”	NA	NA	1	4	2	-	-	-	-	-	-
RADHA	”	NA	NA	1	4	2	-	-	-	-	-	-

INDIA	”	NA	NA	1	9	22	-	-	-	-	-	-
PHOSPHATE												
ZIMIDARA	”	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	-	-
GEE EMM	”	NA	NA	NA	0	9	-	-	-	-	-	-
PARTAP	”	NA	NA	NA	4	1	-	-	-	-	-	-
HARYANA CHEM												
JYOTI CHEM	”	NA	NA	4	3	4	-	-	-	-	-	-
BHUMI SUDHAR	”	NA	NA	3	5	1	-	-	-	-	-	-
A.J. METAL	”	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	-	-
SONA FINE CHEM	”	NA	NA	NA	2	1	-	-	-	-	-	-

CHEMI FERT	”	NA	NA	NA	3	NA	-	-	-	-	-	-
PANT NAGAR	”	NA	NA	NA	NA	3	-	-	-	-	-	-
RELIANCE	”	NA	NA	NA	NA	1	-	-	-	-	-	-
AMAR	”	NA	NA	NA	NA	1	-	-	-	-	-	-
PRODUCTS												
NORTHER	”	NA	NA	NA	NA	3	-	-	-	-	-	-
MINERALS												
MICRO NURTIENTS												

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	5	1	-	-
-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

वर्श 1994 95 का बजट पे ा करना

Mr. Speaker: Now the Finacne Minister will persent the Budjet estimates for the year 1994-95

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, जीरो आवर है।

श्री अध्यक्षः आज बजट पे ा होना है इसलिए आज जीरो पावर नही है।

वित मंत्री श्री मागे राम गुप्ताः माननयी अध्यक्ष महोदय, मै इस गरिमामय सदन के सामने वर्श 1994–95 के बजट अनुमान पे ा करने जा रहा हू।

15.00 बजे

केन्द्र मे वर्श 1991 मे काग्रेस के सत्ता मे आने के साथ ही अहम सरचनात्मक तथा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया आरम्भ हुई। ये सुधार सफफ हुए और गत वर्श अर्थ व्यवस्था की दृढता व स्थिरता का वर्श रहा। विदे ाी निवे ाको ने भारत मे अपनी दिलचस्पी दिखाई और भुगतान के स्थिति मे बडा सुधार आया। उधोगा भी मन्दी की चपेट से निकला और अब इसके उभरने के आसार नजर आने लगे है। गत वर्श के दौरान हर पहलू से दे ा ने निरत्नर प्रगति की और अन्तर्राश्ट्रीय समुदाय मे एक नई छवि और प्रतिश्ठा बनाई।

हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 1993–94

हरियाणा आर्थिक क्षेत्र मे लगातार प्रगति कर रहा है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 1993–94 की प्रतियां माननीय सदस्यो को पहले ही बाटी जा चुकी है, इस मे राज्य मे समूची आर्थिक स्थिति का वर्णन है। मूल्य सूवकांक आधार 1980–81 के मोटे अनुमानो के अनुसार वर्श 1992–93 मे राज्य की अर्थ व्यव्स्था मे 5. 1 प्रति ात की वृद्धि हुई है। वर्तमान मूल्यो पर राज्य का निवल गृह उत्पादन वर्श 1991–92 मे 14551 करोड रूपये से बढकर वर्श 1992–93 मे 16392 करोड रूपये हो गया और इस प्रकार इसमे 12.7 प्रति ात की वृद्धि हुई। तृतीयक, माध्यमिक तथा प्राथमिक क्षेत्रो मे वास्तविक विकास की दर क्रम ा 7.0 प्रति ात 4.5 प्रति ात तथा 4.0 प्रति ात रही। वर्श 1992–93 के दौरान वर्तमान मूल्यो के आधार पर राज्य मे प्रति व्यक्ति आय 9609 रूपये होने का अनुमान है जबकि यह आय वर्श 1991–92 मे 8722 रूपये थी।

राश्ट्र तथा राज्य स्तर पर कीमतो मे वृद्धि दर नियन्त्रण मे रही। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोग्ता मूल्य सूचकांक आधार 1982–100 मार्च, 1992 मे 229 से 6.1 प्रति ात बढकर मार्च, 1993 मे 243 हुआ और उसके बाद 9.1 प्रति ात बढकर नवम्बर, 1993 मे 265 हो गया। इसी प्रकार हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1982–100 मार्च 1992 मे 213 से 7.5 प्रति ात बढकर मार्च 1993 मे 229 हो गया।

वर्श 1993–94 के बजट अनुमानो के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार, चालू वर्श के दौरान 620 करोड के कुल पूजी निर्माण का अनुमान है। इसमे 269 करोड रूपये का सीधा पूजी निर्माण और निजी तथा सार्वजतिन क्षेत्र मे पूजी जुटाने के लिये राज्य सरकार का योगदान 351 करोड रूपये होने का अनुमान है।

विकास नीति

जनता की आ ाए ज्यो ज्यो बढती है। और सरकार पर विभिन्न क्षेत्रो के विकास के लिये दबाव बढता है। तो इस बात की आव यकता होती है कि राज्य मे उपलब्ध साधनो का नए सिरे से अवलोकन करके नए साधानो को ढूढा जाए। सरकार का वह भी अहसास है कि अर्थ व्यवस्थ का सुधार करने के लिए उठाए गए विभिन्ना कदमो के कारण सामाजिक दृश्टि से काफी कीमत चुकानी पडती है और यह सुनिन्ि त करना निहायत जरूरी है कि जन साधारण और वि ोशकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अथवा कमजोर वर्गो पर इनका कुप्रभाव कम से कम हो। हम यह भी समझते है कि जनता से सीधा सम्पर्क राज्य सरकार का रहता है, व यह सुनि ि चत करना भी राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि बाजार मे प्रतिस्पर्धा बढने या साधानो मे कमी होने के बावजूद विकास की प्राथमिकताए बनी रहे व जन कल्याण की योजनए और राज्य का आर्थिक विकास जानी रहे। इस बजट मे इन सभ पहलुओ का ध्यान रखा गया है।

वार्शिक योजना 1993–94

आर्थिक रूप से चालू वर्श अत्यन्त कठिन रहा क्योकि अप्रत्याि ात घटनाओ से साधनो मे हुई कमी और खर्च मे वृद्धि ने राज्य के वित्त पर काफी बोझ डाल दिया। बाढ के कारण राज्य मे बहुत हानि हुई। मन्दी मे केन्द्रीय सरकार का तथा राज्य सरकार के कर राज्सव पर बुरा प्रभाव पडा। परिणामस्वरूप केन्द्रीय करो के हमारे हिस्से मे 24.60 करोड रूपये की कमी आई। बिक्री कर की वसूली मे बजट अनुमानो से 10 करोड रूपए से अधिक की कमी होने की सम्भावना है। कर्मचारियो को कई रियायते दी गई, जिसके परिणामस्वरूप वेतन तथा पें ान का वितीय बोझ बढ गया। राश्ट्रीय ताप बिजली निमम तथा अन्य केन्द्रीय एजेन्सियो के प्रति कुछ बकाया रा ि ा की अदायगी के लिए राज्य बिजली बोर्ड के लिए अतिरिक्त रा ि ा की व्यवस्था करनी पडी। इन वितीय कठिनाइयो के बावजूद विकास की गति को बनाये रखने के लिए सरकार ने 42 करोड रूपए से अधिक के अतिरिक्त साधन जुटाए। केन्द्र मे आर्थिक कर्जे प्राप्त करने के लिए अल्प बचतो मे जमा रा ि ा को बढाने के प्रयास किए गए। इन प्रयासो के परिणामस्वरूप बजट अनुमानो मे दिए गए 125 करोड रूपये के लक्ष्य के मुकाबले मे अल्प बचतो के खाते से 140 करोड रूपये के ऋण प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। राजस्व खाते के खर्च मे किफायत करके व सभी वितीय लेने देन मे सख्त अनु ाासन का परिचय देकर, हम बिना भारी कटौती के विभिन्न विकास योजनाए

चला पाए। बहरहाल, वर्श 1993–94 की वार्शिक योजना के परिव्यय की 920 करोझ रूपये से घटाकर स ाोधित अनुमानो मे 831.43 करोड रूपए किया गया जो कि वार्शिक योजना 1992–93 के 752.46 करोड रूपये के वास्तविक खर्च से 10.5 प्रति ात अधिक है।

वार्शिक योजना 1994–95

वार्शिक योजना 1992–95 तैयार करते समय आठवी पंच वर्शीय योजना मे घोशित लक्ष्यो सामाजिक और सामुदायिक सेवाए बढाने और उनमे सुधार करने, रोजगार के अध्का अवसर बनाने, आधारभूत सरंजचा के विकास तथा कमजोर वर्गो के लोगो के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने पर ध्यान दिया गया है। वितीय कठिनाईयो के बावजूद विकास की गति को कायम रखने तथा तेज करने की जरूरत महसूस करते हुए, वार्शिक योजना 1994–95 के लिए 1025.50 करोड रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। यह वार्शिक योजना 1993–94 के लिए स ाोधित बजट परिव्यय से 23 प्रति ात से भी अधिक है सामाजिक और सामुदायिक सेवाओ के लिए 375.39 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। जो योजना परिव्यय का 36.6 प्रति ात हिस्सा है। आधारभूत सरंचना के विकास की जारी रखने के लिए कुछ परिव्व्यय का 23.1 प्रति ात बिजली के विकास पर, 18.2 प्रति ात सिचाई पर और 2.2 प्रति ात सडको पर खर्च किया जाएगा। खर्च का 7.3 प्रति ात

हिस्स कृशि और सम्बद्ध कार्यो के लिए है ंराज्य सरकार अर्थ व्यवस्था मे विविधता लाने और द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रो मे अं ादान बढाने के लिए गहन प्रयास कर रही है ताकि अर्थ व्यवस्था पुख्ता हो सके और इसमे आव यक लचीलापन आ सके। हमे वि वास है कि चरणबद्ध ढंग से इनता भारी निवे ा न केवल आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने मे बल्कि अर्थ व्यवस्था के विकास की गति को बढाने और समाज के कमजोर तथा पिछडे वर्गो के जीवन स्तर को बेहतर मे भी सहायक होगा।

आपद राहत

राज्य मे इस वर्श के दौरान मौसम ज्यादा अनुकूल नही रहा। जुलाई 1993 के कुछ दिन लगातार वर्शा से राज्य के बहुत से भागो मे भारी बाढ आई। पजाब मे बाढ का पानी आ जाने से समस्या और भी गम्भीर हो गइ। 1105 गावो तथा 13 नगरो, मे 4. 6 लाख हैक्टैयर क्षेत्र जिसमे 1.33 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र भाामिल है और 4.6 लाख हैक्टेययर क्षेत्र जिसमे 1.33 लाख हैक्टेयर क्षेत्र भाामिल है और 14.26 लाख लोगो पर बाढ का भारी असर रहा। इससे 50 व्यक्तियो और 596 प ुओ की जाने गई। सरकार को तुरन्त भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधा देकर राहत पहुचाई और लोगो को सुरक्षि सीानो पर पहुचाया। थल सेना और वायु सेना से भी सहायता प्राप्त की गई। भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया गया जिसमे 205.56 करोड रूपये केन्द्रीय राहत अनुदान मांगा गया केन्द्रीय सरकार ने खर्च 1994–95 के

लिए आपद राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से से 6.38 करोड रूपये पे ागी दिए है। बाढ राहत उपायो के लिए 16.60 करोड रूपये और क्षति ग्रस्त लोक निर्माण कार्यो के सुधार और मरम्मत के लिए 30.79 करोड रूपये की रा ि ा दी गई है मृतक व्यक्तियो के निकटतम सम्बन्धी को दी जाने वाली अनुग्रही राहत रा ि ा 10000 रूपये से बढाकर 50000 रूपये कर दी गई । प ु हानि व मकानो के नुकासान के लिए मुआवजे तथा कृशि उपयोगी पदार्था पर सब सिडी की दरो से भी उचित वृद्धि की गई। वितीय सस्थानो मे भी बाढ प्रभावित किसानो को राहत देने मे राज्य सरकार को सहयोग दिया। किसानो के छोटी अवधि के कर्जो को मध्यम अवधि के कर्जो मे बदल दिया गया। बाढ रोकने के उपायो के लिए सरकार ने रावी घग्घर तथा सिकन्दपुर नालो के निर्माण का भी निर्णय लिया है । इसके लिए 1.52 करोड रूपये की रा ि ा की स्वीकृति भी दे दी गई है। विभिन्न आपद राहत उपायो के लिए 47 करोड रूपये से अधिक रा ि ा खर्च की गई।

दसंवा वित आयोग

माननीय सदस्यगण हस बात से परिचित ही है कि राज्यो की वितीय आव यकताओ का अनुमान लगाने और केन्द्र से राज्यो को निधियो के अन्तरण के लिए सिफारि ो करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दसवे वित आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने वर्श 1995 से 2000 के दौरान करो के बटवारे और सहायता अनुदान के लिए विस्तारपूर्वक दलीले देते हुए आयोग

के विचारर्थ ज्ञापन दे दिया है। प्र ासन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाए भी पे ा की है जिनके लिए उस अवधि के दौरान 2322 करोड रूपये रा ि ा की आव यकता होगी। हमने राज्य की वि ोश समस्याओ के लिए 3425 करोड रूपये के अनुदान की भी मांग की है। आयोग द्धारा विचार विर्म ा के लिए निकट भविश्य मे राज्य का दौरान किया जाएगा। सम्भव है कि वे राज्य के विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रति निधियो से भी भेट करे। माननीय सदस्यो से मेरा अनुरोध है कि वे भेंटवार्ता के समय राज्य को अधिक वितीय सहायता देने के लिए जोरदार दलील पे ा करे।

73 वा तथा 74 वां स ाोधन

माननीय सदस्यो को विदित है कि संसद द्वारा सविधान 73 वा स ाोधन अधिनियम बनाया गया है। दे ा भर मे ग्राम पचायतो का एक समान त्रिस्तरीय ढांचा भाुरू किया जा रहा है। और पचायतो की समय अवधि अन्य प्रजातात्रिक सस्थाओ के समान पांच वर्श नियत कर दी गई है। अधिनियम मे महिलाओ औरा समाज के कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। सविधान के इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यो मे पंचायतो की वितीय स्थिति का पुनर्विलोकर और राज्य निधियो पचायतो को अन्तरित करने के बार मे सिफारि ो करने के लिए राज्य वित आयोग, व पचायतो के चुनाव की प्रक्रिया सुपरवाइज करने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना हैं राज्य सरकार जल्दी ही

इन आयोगो का गठन करेगी। सविधान 74 वा स ाोधन अधिनियम के अन्तर्गत इसी प्रकार का प्रावधान नगर निकायो के लिए भी किया गया है।

बिजली

सरकार इस तथ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक है कि आर्थिक विकास गति को बनाये रखने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाना अति आव यक है। चालू वर्श के दौरान बिजली की स्थिति थोडे सकय के लिए कुछ नाजुक रही। पहले बाढ और फिर मानसुन के दौरान लगभग सूखे के कारण भाखडा और पौग परियोजनओ से बहुत कम बिजली प्राप्त हुई । तथाति कृशि और अन्य क्षेत्रो के लिए हरियाणा राज्य बोर्ड ने महगी दरो पर बिजली की खरीद राज्य के बाहर से की। इसके परिणामस्वरूप कम वर्शो के बावजूद खरीफ की फसल बहुत अच्छी हुई । आ ाा है रबी की फसल भी इस प्रकार अच्छी होगी।

माननीय सदस्यगण, आप इस बात से अवगत है कि कुल उपलब्ध बिजली का 50 प्रति ात से अधिक हिस्सा कृशि क्षेत्र को पचास पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर सप्लाई किया गया है जबति उपभोग्ता तक बिली पहुचाने की वास्तविक लागत 1.31 रूपये प्रति यूनिट पडती हैं उपलब्ध बिजली का बहुत बडा हिस्सा कृशि क्षेत्र को रियासतो दरो पर सप्लाई करने के कारण बिजली

बोर्ड को भारी हानि हो रही है। वर्श 1992–93 मे हरियाणा राज्य बोर्ड को 335.36 करोड रूपये की कुल कामर्ियल हानि हुई है।

बिजली उत्पादन बढाने और वितरण प्रणाली मे सुधार करने के गहन प्रयापस किये जा रहे है अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जुटाने के लिए भारी निवे ा की आव यकता है। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा मे बिजली क्षेत्र मे '' सुव्यवस्था एवम निवे ा अध्ययन'' किया जाये। इसके लिए वि व बैक से 20 लाख अमरीकी डांलर कर्ज लिया जायेगा। इस अध्ययन की सिफारि ाो से हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की कार्यकु ालता बढाने और वि व बैक से बिजली के लिए पर्याप्त वितीय मदद प्राप्त करने मे सहायता मिलेगी।

वर्श 1994–95 के दौरान बोर्ड की वितीय स्थिति मे सुधार लाने के लिए बजट मे 105 करोड रूपये की नकद ग्रामीण बिजलीकरण सबसिडी का प्रवाधान किया गया है। सरकारी विभागो से देय बकाया 425 करोड रूपये के बिजली बिलो का समायोजन हरियाणा बिजली बोर्ड को दिय गये कर्जो की प्राप्तियो के साथ किया जा रहा है। बिजली के पारेशण और वितरण नैट बर्क मे सुधार लाने और पानीपत थर्मल परियोजना के छठे यूनिट को पूरा करने के लिए वर्श 1994–95 के दौरान सरकार ने बिजली क्षेत्र मे 236.88 करोड रूपये के निवे ा की योजना बनाई है।

वाक आउट

इस समय सदन मे उपस्थित जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य बजट की तथाकथित लीकेज के विरोध मे वाक आउट कर गये।

वर्श 1994– 95 का बजट पे ा करना (पुनरारम्भ)

वित मंत्री (श्री मागे राम गुप्ता)

सडक सरंचना

सरकार उधोग एमव कृशि दोनेा क्षेत्रो के समूचे विकास के लिए थल परिवहन के पर्याप्त व कु ाल आधारभूत ढाचे के महत्व हो समझाती है। राज्य की सडके दे ा भर मे सर्वोतक मानी जाती है। जून 1991 म हमारी सरकार बनने के प चात सडको की मुरम्मत तथा देख रेख राज्य मे राश्ट्रीय राजमार्गो की फोरलेनिग, नई सडको तथा पुल का निर्माण करने तथ भविश्य मे कार्योन्वित की जानी वाली नई परियोजना बनाने पर जोर दिया गया। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्श हो रहा है कि इन सभी पहलुओ पर प्रगित हुई है। 402 किलामीटर लम्बी सडको का निर्माण हुआ है, विधमान 6166 किलोमीटर लम्बी सडको पर नई परत चढाई गई है और 757 किलोमीटर लम्बी सडको मे सुधार किया गया है। चूकि सडको का निर्माण पूजीगत कार्य है, अत हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड को भी इस कार्य मे लगाया गया है।

राश्ट्रीय राजमार्ग न0 1 मुरथल से करनाल तक चारमार्गो बनाने के कार्य मे अच्छी प्रगति हुई है और 25 किलोमीटर लम्बी सडक को यातायत के लिए खोल दिया गया है। कुल 50 किलोमीटर लम्बी सडक के जून 1994 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। करनाल अम्बाला भाग का कार्य भीघ्र ही भुरू किया जाएगा। बल्लबगढ से होडल तक राश्ट्रीय राजमार्ग न0 2 की फोरलेनिग दिसम्बर, 1995 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। गुडगांव से राजस्थान सीमता तक राजमार्ग न0 8 को चारमार्गो बनाने का कार्य एि ाय वि व बैक की 160 करोड रूपये की आर्थिक सहायत से भुरू किया जाएगा। बहादुरगढ से रोहतक तथ आगे फतेहबाद तक राश्ट्रीय राजमार्ग न0 10 को चारमार्गो बनाने की परियोजना अनुमोदनार्थ थल परिवहन मन्त्रालय को भेजी गई है। अम्बाला यमुनानगर से दिल्ली तक एक नया एक्सप्रैस हाईवे बनाने का प्रस्ताव है। 437 करोड रूपये की लागत से 811 किलोमीटर लम्बी सडके बनाने की राज्य सडक परियोजना वि व बैक द्वारा सैद्वान्ति रूप से स्वीकार कर ली गई है।

गत अढाई वर्शो के दौरान 21 पुला का निर्माण किया जा चुका है। चालू वर्श के दौरान मारकण्डा नदी पर अम्बाला कैथल सडक पर जलबेडा मे यमुना नदी पर करनाल मेरठ रोड पर व पि चमी यमुना नहर पर कर्ण झील के निकट राश्ट्रीय राजमार्ग न0 1 पर पुलो के निमार्ण कार्य को पूरा कर लिया गया है। यातायत के प्रवाह को सुचारू एवम बिना रूकावट चलाने के लिए

पानीपत मे दो, तथा सोनीपत, बडखल और हिसार मे एक एक, कुल पांच औवर ब्रीज का निर्माण किया जा रहा है। मोरनी त्रिलोकपुर रायपुरानी सडक पर टागरी नदी पर और बरोटीवाला के निकट सिरसा नदी पर पुलो का निर्माण जारी है। रिवाडी तथा बल्लभगढ मे दो ओवरब्रीज बनाने का कार्य योजना स्तर पर है।

सिचाई

कृशि मे लगातार वृद्धि को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाये बिना जारी नही रखा जा सकता। हरियाणा मे भूगत जल लगभग समाप्त होता जा रहा है। अब सिचाई का और अधिक विस्तार मुख्य तौर पर सतलुज यमुना लिंक नहर, जो कि राज्य की जीवन रेखा है के पूरा होने पर निर्भर करता हैं । पजाब मे बिगडे हालात के कारण नहर के निर्माण मे कुछ अनाव यक विलम्ब हुआ है। हमारी सरकार नहर के भीघ्र निर्माण के लिए पूरी तरह से बचनबद्ध है और हम भारत सरकार व पजाब सरकार से इस विशय मे लगातार वार्तालाप कर रहे है। हमे आ ाा है कि पजाब मे कानून और व्यवस्था मे सुधार होने से नहर का निर्माण कार्य जल्दी दोबारा भाुरू होगा। और भीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उपलब्ध पानी के यथोचित इस्तेमाल के लिए सारी नहर व्यव्सथा का उचित रख रखाव आव यकत है। इस प्रयोजन हेतु वर्श 1994–95 के बजट अनुमानो मे 14.82 करोड रूपये का प्रावधान रखा गया है। हरियाणा के सतलुज यमुना लिंक नहर के हिस्से और पजाब के

साझे जल मार्गो के रख रखाव के लिए भी प्रवाधान किया जा रहा है।

सिचाई की क्षमता को बढाने के लिए पानी की रिसन हानि कम करने हेतु नहरो तथा जलमार्गो को पक्का करने की विभिन्न परियोजनाए सिचाई विभाग, कमाण्ड ऐरिया, विकास प्राधिकरण और लघुसिचाई तथा नलकूप निगम द्वारा चलाई जा रही है। वर्श 1993–94 के दौरान 200 लाख वर्ग फुट कच्चे जलमार्ग क्षेत्र को 35.19 करोड रूपये की लागत से पक्का किया जाएगा, जिससे 110 क्यूसिक जल बचेगा और 32000 एकड भूमि मे अतिरिक्त सिचाई हो सकेगी।

वि व बैक द्वारा वर्श 1994–95 के दौरान ''जल स्त्रोत समेकन परियोजना'' नाम की एक नई परियोजना मजूर किये जाने की सम्भावना है। इसके अन्तर्गत भोश जलमार्गो को पक्का करने, रिसन हानि को रोकने और खारे क्षेत्रो के सुधार के लिए भूगत जल निकास और जल क्षमता को बढाये जाने का लक्ष्य है। यह परियोजना 6 वर्श की अवधि मे क्रियान्वित की जाएगी और इस पर कुल 800 करोड रूपये की लागत आने का अनुमान है। 1994–95 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए वाार्शिक योजना मे 93.30 करोड रूपये का प्रावधान है।

हरियाणा के लिए यह गर्व की बात है कि राजस्थान सरकार ने 40.21 करोड रूपये की अनुमानित लागत की सिद्धमुख

नोहर फीडर परियोजना के निर्माण के लिए हरियाणा सिचाई विभाग को सेवाए ली है। यह मुख्य तथा मध्यम सिचाई परियोजना लगाने मे हमारी तकनीकी क्षमता का सूचक है।

लघु सिचाई के अन्तगर्त चालू वर्ग के दौरान 30.57 करोड रूपये की लागत से 960 किलोमीटर लम्बे 210 जलमार्गो को पक्का किया जाएगा। इससे 6880 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि मे सिचाई हो सकगी। वर्श 1994–95 के दौरान 1136 किलोमीटर लम्बे जलमार्गो को पकका करने के लिए 29 करोड रूपये का प्रावधान यिका गया है सरकार इस बात से पूरी तरह अवगत है कि केवल सिचाई क्षमता बढाना ही काफी नही। अतः हम कमाण्ड एरिया के विकास को वि ोश महत्व दे रहे है जिसके लिए वर्श 1994–95 की वार्शिक योजना मे 25.30 करोड रूपये का उपबन्ध किया गया है। चालू वर्श के दौरान 23 करोड रूपये की लागत से 21 लाख फुट लम्बे जलमार्गो को पक्का किया जाएगा और 31700 हैक्टेयर क्षेत्र मे वारवंदी भ्रारू की जाएगी। भारत सरकार के अनुमोदन से आगरा नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र और प ि चम यमुना प्रणाली के कुछ अतिरिक्त कमाण्ड क्षेत्र को भी कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत लाया गया है।

कृशि तथ सम्बद्ध कार्य

कृशि के क्षेत्र से हमारी प्रगति उल्लेखनीय रही है। वर्श 1966 मे हरियाणा राज्य मे खाधान्न की कमी थी, किन्तु अब यह

दे ा का खाधन्न भण्डार बन गया है। माननीय सदस्यो को मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि वर्श 1993–94 के दौरान हरियाणा राज्य मे केन्द्रीय खाधान्न पूल मे 34.54 लाख टन गेहू दिया। पिछले तीन वर्शो से हरियाणा राज्य लगातार भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक चालव केन्द्रीय पूल मे दे रहा है। वर्श 1993–94 के केन्द्रीय पूल के लिए नियम 7.5 लाख टन चावल के लक्ष्य के मुकाबले फरबरी, 1994 तक 11.61 लाख टन चावल दिया जा चुका है। माननीय सदस्यो को याद होगा कि वर्श 1993–94 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय मैने यह वि वासपूर्वक कहा था कि हमारा राज्य 1.00 करोड टन से अधिक खाधान्न पैदा करके नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुझे इस गरिमामय सदन को यह बताते हुए प्रस्नना हो रही है कि राज्य वर्श 1993 –94 के दौरान 103.50 लाख टन खाधान्न उत्पादन के लक्ष्य के मुकाबले, 105 लाख टन उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अग्रसर है। चालू वर्श के दौरान 7.0 लाख टन गुड कपास की 13 लाख गाठे और सूरजमुखी समेत 7.6 लाख टन तिलहन का उत्पादन होने की सम्भावना है।

हम किसानो को व्यापक उत्पादन आधार प्रदान करने के लिए खेतीबाडी मे विविधता लाने के प्रयाय कर रहे है गन्ना, कपास और तिलहन जैसी नकद फसलो की खती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूरजमुखी को का त को बढावा दिया जा रहा है। और चालू वर्श मे 50.000 हैक्टेयर क्षेत्र मे इसकी खेती किए

जाने की आ ाा है राज्य मे सोयबान और राजमा ा की नई फसलो की खेती भी भाुरू की गई है।

मै पहले भी यह कह चूका हू कि मानसून के दौरान राज्य मे बहुत से भाग बाढ से प्रभावित हुए। इससे 1.33 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे खरीफ फसलो का नुकसान हुआ। बाढ पीडित किसानो की मदद के लिए सरकार द्वारा 160 रूपये प्रति एकड दर से कृशि उपयोगी वस्तुओ पर सबसिडी दी गई। इसके लिए 5 करोड रूपये का प्रावधान किया गया था। हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा कृशि कार्यो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियो को राहत दी जाती है, इसमे मृत्यु की स्थिति मे 30000 रूपये ओर अग्रहीन होने की स्थिति मे 12000 रूपये तक अनुदान दिये जाते है अब तक कृशि दुर्घटना के ि ाकार 1799 व्यक्तियो को 2.15 करेाड रूपये के ऐसे अनुदान दिये गए है। किसानो को बीज, उर्वरको, कीटना ाी, खरपतवार ना ाक, पानी, जिप्सम और दूसरे इन्पुटो पर सीधी सबसिडी नियमित आधार पर दी जाती है। रासायनिक खादो के उपयोग को बढावा देने के लिए भारत सरकार से प्राप्त 7.41 करोड रूपये की रा ि ा किसानो को खाद पर सबसिडी के रूप मे वितरित की गई है। इन सभी उपायो के परिणामस्वरूप खाद की खपत 1992–93 मे 6.63 लाख टन से बढकर वर्श 1993–94 मे लगभग 7.3 लाख टन हो गई। वर्श 1994–95 के लिए खाद की बढत का लक्ष्य 8.18 लाख टन नियत किया गया है।

वर्श 1994–95 के लिए 107 लाख टन खाधन्न, 9 लाख टन गुड, 15 लाख कपास की गाठे और 8.85 लाख टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया है।

राज्य की अनेक एजेसियो खेतो के भूमि सुधार कार्यक्रमो मे लगी हुई है। राज्य की खारी भूमि के सुधार के लिए 15.26 करोड रूपये की कुल लागत वाली एक पायलट परियोजना वर्श 1994–95 मे क्रियान्वित की जाएगी। इसके लिए डच सरकार से तकनीकी और 90 प्रति ात वितीय सहायता मिलेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत सोनीपत जिले से जवाहर लाल नेहरू और कैथल जिले के कलायत क्षेत्र मे भाखडा नहर के कमाड क्षेत्रो की सेम और खारेपन से प्रभावित भूमि मे म ीनो से समतल भूगत निकास व्यवस्था लगाने सम्बन्धी तकनीक का अन्तरण किया जाएगा। समेकिट वाटर भौड विकास पहाडी परियोजना, काण्डी क्षेत्र भरी मार्च 1990 से अम्बाला और यमुनानगर जिलो की तराई मे 1.92 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के समेकित विकास के लिए चलाई जा रही है इस परियोजना के लिए वर्श 1993–94 के लिए 4.60 करोड रूपये और 1994–95 मे 5.30 करोड रूपये का परिव्यय रखा गया है हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम भी रिहायसी जिप्सम के वितरण और भूमि समतलन आदि द्वारा भूमि सुधार कार्यो मे लगा हुआ है।

कृशि उत्पादन मे हो रही असाधारण वृद्धि के दृश्टिगत आव यक भण्डारण और विपणन नैट वर्क की व्यवस्था का महत्व

भ बढ गया है। हरियाणा वेयर हाउसिंग निगम कुल 9.6 लाख टन क्षमता के 104 भण्डारण्गृह चला रहा है। वर्श 1993–94 के दौरान इस क्षमता मे 5670 मीट्रिक टन और 1994–95 मे 9000 मीट्रिक टन की बढत की जाएगी। हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड, मार्केट यार्ड, खरीद केन्द्र और जिलक सडको के निमार्ण से राज्य मे फसल मार्केटिग नैट वर्क को सुदृढ बना रहा है। 100 मुख्य यार्ड, 175 उप यार्ड तथा 135 खरीद केन्द्र बन चुके है जिससे किसानो को अपने गाव के 5 से 7 किलोमीटर घेरे के अन्दर ही फसल बेचने की सुविधा उपलब्ध है।

बागवानी

वर्श 1990 मे अलग बागवानी निदे ालय बनने और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मे विविधता आने से बागवानी विकास अब गति ील हो गया है। वर्श 1990 के प चात राज्य मे सब्जियो तथा फलो की का त के अधीन क्षेत्र मे लगभग 50 प्रति ात वृद्धि हुई है। खुम्भी उत्पादन, फूलो की खेती और ड्रिप सिचाई तथा पालीग्रीन हाउस जैसे नई तकनीको को भुरू करने की और वि ोश ध्यान दिया जा रहा है।

प ुधन

हमारा वि वास है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के एकीकृत विकास के लिए प ुधन का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अत हम प ु चिकित्सा हस्पतालो और डिस्पैसरियो के व्यापक नैट वर्क के

माध्यम से नस्ल सुधार, सतुलित भोजन और असरदार स्वास्थय रक्षा जैसे प ाुपालन का कार्य करने पर जोर दे रहे है। 7 जिलो मे एकीकृत प ा विकास परियोजना लागू की जा रही है। 536 प ा चिकित्सा हस्पतालो, 762 प ा चिक्त्सा डिस्पैसरियो, 60 क्षेत्रिय कृत्रिम वीर्य सेचन केन्द्रो और 758 स्आकमैन केन्द्रो के वर्तमान प ा स्वास्थय नैट वर्क को, 200 नई प ा चिकित्सा डिस्पैसरियां खोलकर और 10 प ा चिकित्सा डिस्पैसरिया का दर्जा बढाकर उन्हे हस्पातल एवम प्रजनन केन्द्र बनाकर सुदृढ किया जाएगा। गुडगाव मे एक पालीकिलनिक भी खोला जाएगा। इस क्षेत्र के लिए वर्श 1994–95 मे 6.33 करोड रूपये की योजनागत व्यवस्था की गई हैं।

सहकारिता तथा उधार

माननीय सदस्य मुझे से सहमत होगे कि कृशि तथा सम्बद्ध कार्यो को बढावा देने मे सहकारिता आन्दोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य की सहकारी वि सस्थाए किसानो एवम लघु तथा छोटे ग्रामीण उघोगो की ऋण आव यकताओ को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है । राज्य की विभिन्न सहकारी सस्थाओ ने पहली अप्रैल 93 से 31 दिसम्बर, 93 तक 660.37 करोड रूपये की फसल कर्जे, 32.21 करोड रूपये के गैर कृशि कर्जे, अनुसूचित जातियो, पिछडे वर्गो तथा ग्रामीण कारीगरो के लिए 123.01 करोड रूपये के कर्जे और कृशि विकास के लिए 67.29 करोड रूपये की लम्बी अवधि के कर्जे दिए। कर्जो की वसूली मे भी सुधान हुआ है

और विभिन्न सस्थाओ मे 62.5 प्रति ात से 77.7 प्रति ात तक वसूली हो रही है। वर्श 1993–94 के दौरान बाढ से प्रभावित किसानो की सहायता के लिए सहकारी बैको ने 28.44 करोड रूपये के छोटी अवधि के कर्जो को मध्यम अवधि कर्जो मे बदल दिया। वर्श 1994–95 के दौरान सहकारिता क्षेत्रो के लिए योजना पक्ष मे 4.89 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।

उधोग

आर्थिक प्रगति के लिए उधोगीकरण अनिवार्य है। राज्य के त्रीव उधोगीकरण के लिए सरकार ने अनेक नीति निर्णय लिये है। पहली अप्रैल 92 से नई औधोगिक नीति अपनाई गई थी जिसमे कृशि आधारित खाध संसाधन उधोगो और इलकट्रानिक उधोगो को थर्स्ट एरिया माना गया है। पिछडे क्षेत्रो मे उधोग लगाने के लिए जनरेटर सैटो के लिए सबसिडी देने के अतिरिक्त बिजली भ्ाुल्क और चुगी से छुट, बिक्री कर से छुट, तथा आस्थगन और मूल्य प्राथमिकता जैसी आर्थिक प्रोत्साहन दिए जा रहे है । विदे ाी तथा प्रवासी भारतीय निवे ा जुटाने के लिए वि ोश अभियान भी भ्ारू किया गया है। राज्य को ऐसे 246 प्रस्ताव प्राप्त हुए है और 176 औधोगि प्लाट प्रवासी भारतीयो को अलाट किये गये है 33 यूनिटो मे उत्पादन कार्य भ्ारू हो चुका है।

सतुलित क्षेत्रीय उधोगीकरण को बढावा देने के लिए 76 विकास खण्डो को पिछडा क्षेत्र घोशित किया गया है। औधोगिक

रूप से पिछडे क्षेत्रो मे 10 औधोगिक सम्पदाए और 2 विकास केन्द्र सीापित किए जाएगे। चालू वर्श के दौरान, 160 करोड रूपये के निवे ा से 45 बंडे तथा मध्यम औधोगिक यूनिट और लघु क्षेत्रो मे 6422 यूनिट लगाए गए थे। अनेक उधमकर्ताओ ने हरियाणा मे परियाजेनाए सीापित करने हेतु भारत सरकार को औधोगिक उधमर्ता ज्ञापन दिए है। इनमे से 117 यूनिट चालू हो चुके है और 107 यूनिट चालू होने वाले है। गुडगांव मे जापान की सहायता से एक माडल औधोगिक टाउनि ाप सीापित किया जाएगा। उन्नत तकनीकी और प्रदुशण रहित उधोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

इलैक्ट्रानिक्स के विाकस के लिए वर्श 1994–95 के दौरान 3.08 करोड रूपये के योजनागत परिव्यय का उपबन्ध किया गया है। पचकूला मे भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटिड के लिए इलैक्ट्रानिक्स सहायक खण्ड सीापित किया गया है। यू0एन0डी0पी0 की सहायता से सीापित की जा रही ''प्रिसिजन मैडिनिकल डिजाइन एण्ड असिस्टिड फेसिलिटीज''परियोजना के अन्तगर्त पर्याप्त हुई है। गुडगावं मे एक इलैक्ट्रानिक सिटी सीापित करने के सम्बन्ध मे सतोशजनक प्रगति हुई है और 32 फलैटिड फैक्ट्री माडयूल का निर्माण पूरा हो चुका है।

पिछडे क्षेत्रो के उधोगीकरण के लिए भारत सरकार ने राज्य मे दो विकास केन्द्र सीापित करने की स्कीम अनुमोदित की है। इन विकास केन्द्रा का उददे ाय पिछडे क्षेत्रो मे बिजली, पानी,

दूर संचार आदि आधारभूत सुविधाए देकर वहा उधोगीकरण को बढावा देना है। इन दो विकास केन्द्रो को सीापित करने की जिम्मेदारी हरियाणा राज्य औधोगिक उधोगो विकास निगम को सौपी गई है।

राज्य के गावो मे उधोग कुज नामक लघु विकास सम्पदओा का भी विकास किया जा रहा है। भुरू मे ऐसी सम्पदाए गुडगाव, सोनीपत, हिसार और रोहतक के चार जिलो मे सीापित की जाएगी। वर्श 1994–95 के दौरान उधोग के लिए 27.64 करोड रूपये का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है।

औधेगिक वित सस्थाए

हमे वि वास है कि उधोगो के विकास के लिए प्रोत्साहनो और रिहायतो की व्यवस्था करने के साथ साथ सुदृढ आधारभूत ढाचा तथा वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है जिसकी व्यवस्था प्रभावी वित्तीय सस्थाओ द्वारा की जाती है। हरियाणा राज्य औधोगिक विकास निगम, हरियाणा राज्य वित निगम, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम, तथा हरियाणा कृशि उधोग निगम मे चार सस्थाए उधोगो को ईक्बिटी भागीदार तथा मध्यम एवम लम्बी अवधि के कर्जो के रूप मे आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है वर्श 1993.94 के दौरान हरियाणा राज्य औधोगिक विकास निगम ने कई परियोजनाए स्थापित करने के लिए प्राइवेट पार्टियो के साथ 10 समझौतास ज्ञापन पत्रो और 11

वित्तीय सहयोग समझौतास पर हस्ताक्षर किए है। जिन मे 8.28 करोड रूपए की ईक्विटी भागीदारी होगी और कुल 196 करोउ रूपए का निवे ा निहित होगा। निगम ने उपकरणो की पटटेदारी का भी कार्य भाुरू कर दिया है औश्र यह पहली राज्यस्तरीय संस्था है जिसे मर्चेण्ट बैकर के रूप मे भारतीय स्टाफ एक्सचेज बोर्ड द्वारा प्रथम कैटेगरी का प्राधिकार दिया गया है भावी उधमकर्ताओ को राज्य मे सभी सुविधाए एक स्ाान पर ही जुटाने हेतु निगम किराया खरीद तथा बिलो मे हुण्डावन की सेवा प्रदान करने की योजना भी तैयार कर रहा है। हरियाणा वित निगम ने दिसम्बार 1993 तक 83.38 करोड रूपए के साबधि ऋण मजूर किए है और वर्श 1994–95 के दौरान 200 करोड रूपए के कर्जे मजूर करने व 162 करोड रूपये के कर्जे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा कृशि उधोग निगम ने कृशि पर आधारित तथा खाधान्न संसाधन के यूनिट स्ाापित करने के लिए 6 समझौता ज्ञापन पत्रो पर हस्ताक्षर किए है।

सार्वजनिक उधम

राज्य मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 48 उधम विभिन्न व्यापार, सेवा कल्याण तथा वितीय गतिविधियो मे सलग्न है। हरियाणा सार्वजनिक उधम ब्यूरो ने विभिन्न सार्वजनिक उधमो की वितीय क्षमता सुधारने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई भी सार्वजनिक उपक्रम इस ब्यूरो की पूर्व स्वीकृति के बिना अतिरिक्त पदो का सृजन अथावा अपने कर्मचारियो के वेतनमानो मे सं ाोधन

नही कर सकता। ब्यूरो इन उधमो के कार्य को मानीटर करता है और उनको समीक्षा करता है। इसने महत्वपूर्ण वितीय पैरामीटरो के आकडा आधार तैयार किए है।

सस्थागत वित तथा राज्य ऋण योजना

सस्थागत वित तथा राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के वि ोश भूमिका निभाता है। वर्श 1993–94 मे राज्य की वार्शिक ऋण योजना मे 1217.6 करोड रूपए के ऋण की परिकल्पना है जो कि गत वर्श की ऋण योजना से 29.7 प्रति ात अधिक है। वर्श 1992.93 के दौरान हरियाणा मे वाणिज्यिक बैको तथा अन्य वितीय संस्थाओ ने 1347.35 करोड रूपए के ऋण दिए जबकि वर्श 1991–92 के दौरान 861.40 करोड रूपए के ऋण दिए गए थे। इस ऋण मे से 78 प्रति त प्राथमिक क्षेत्र, 15.8 प्रति ात द्वितीय क्षेत्र, तथा 6 प्रति ात तृतीय क्षेत्र के लिए था। 31 मार्च, 1993 को दिए गए कर्जो तथा जमा धन का अनुपात 55.18 प्रति ात था और 5277 करोड रूपए के जमा के मुकाबले बकाया पे ागी 2912 करोड रूपए थी।

मैने पहले भी कहा है कि राश्ट्रीय कृशि एवम ग्रामीण विकास बैक तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैको ने बाढ पीडितो को राहत देने के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान किया है। बैको से बाढ के दौरान क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियो के सुधार, मुरम्मत तथा पुनिर्माण के लिए ऋणो की व्यवस्था की। हमे वि वास है कि

बैक तथा अन्य वित्तीय संस्थाए राज्य मे विकास की गति को तीव्र करने के लिए राज्य सरकार को पूरा समर्थन देती रहेगी।

पर्यटन

हरियाणा ने पर्यअन को उधोग के रूप मे विकसित करने मे अपनी एक अलग पहचान बनाई है, हालाकि राज्य मे कोई भी प्राकृतिक पर्यअन स्थल नही है। राज्य मे 43 पर्यटन केन्द्र है। चालू वर्श के दौरान राज्य ने एक लाख से अधिक विदे ाी पर्यटको तथा 42 लाख से अधिक दे ाी पर्यटको का सत्कार किया है। इस वर्श पचकूला तथा फतेहबाद मे दो नये पर्यटन केन्द्रो का निर्माण किया गया है। हिसार तथा यमुनानगर मे दो और ऐसे पर्यटन केन्द्र निर्माणाधीन है। एक अलग प्रकार का पर्यटन केन्द्र ''एथनिक इण्डिया'' सोनीपत के निकट राई मे बनाने का प्रस्ताव है। वर्श 1994–95 मे पर्यटन सुविधाओ के विकास के लिए 3.20 करोड रूपये खर्च किए जाएग। हम इस क्षेत्र मे निवे ा करने के लिए निजी क्षेत्रो को भी प्रोत्साहित कर रहे है। और अब तक 14 निजी पर्यटन केन्द्र खुल चुके है।

वन और पर्यावरण

वनो के अधीन और अधिक क्षेत्रो को लाने के लिए राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रो मे अनेक स्कीमे चलाई जा रही है। वर्श 1994–95 के दौरान ई0ई0सी0 द्वारा लगभग 75 करोड रूपये की लागत की बजर भूमि वानिकी और कृशि वानिकी परियोजना के

परखे और अनुमोदित किये जाने की सम्भावना है वानिकी कार्यो को और बढावा देने के लिए वर्श 1994–95 की वार्शिक योजना मे 29.18 करोड रूपये का प्रवाधान किया गया है।

पर्यावरण सरंक्षण और परिवे ा व्यवस्था पर पिछले कुछ वर्शो से वि ोश ध्यान दिया जा रहा है राज्य मे वर्श 1984 मे पर्यावरण विभाग बनाया गया था, जो राज्य मे परिवे ा सतुलन के सरंक्षण और सुधार के लिए अनेक कार्य कर रहा है। राज्य स्तरीय पराम र्ी प्रयोग ाला एमव आम एफलुएंट भाोधन सयन्त्र कुडली उधोग सम्पदा मे सीापित किए गए है। इसी प्रकार के आम एफलुएंट भाोधन संयत्र वर्श 1994–95 के दौरान अम्बाला, मूरथन और जीन्द मे सीापित किये जायेगे। पयोवरण सरंक्षण, प्रदुशण नियत्रण और वन्य प्रणाी सर्क्षण सम्बन्धी विभिन्न नियमो का सख्ती से अनुपालन सुनि चत करने हेतू सरकार का राज्य के मण्डलीय मुख्यमलयो मे 4 वि ोश पर्यावरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्श 1994–95 मे पर्यावरण संरक्षण के लिए 1.10 करोड रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सडक परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन दे ा के सर्वोतम परिवहन उपक्रमो मे से है। वर्श 1993–94 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यचालन मे ईधनो क्षमता, लोड फैक्टर और प्रति किलोमीटर आय मे और भी सुधार हुआ है। बस व्यवस्था को बेहतर बनाने के

लिए अनेंक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ किये गये है। जैसे डिपो का कम्प्यूटरीकरण केन्द्रीय इजंर औवर हालिक वर्क ाप की स्थापना, वर्क ाोपो मे फलोटिग लाइन असैम्बली की व्यवस्था, बसो धोन के लिए स्वचालित म ाीने लगाना और प्रदुशण नियन्त्रण उपकरो की व्यवस्था आदि। वर्श 1994–95 के दौरान 548 बसो को बदलने के लिए 34.73 करोड रूपये की रा ि ा का प्रावधान किया गया है। माननीय सदस्यो को याद होगा कि योजना आयोग इस बात से सहमत नही हो रहा है कि राज्य परिवहन उपक्रमो की बसो की सख्या मे वृद्धि की जाये। जनता की स्थानीय परीवहन की मांग को पूरा करने के लिए हम ने गत वर्श बेरोजगार युवको को सहकारी समितियो को लिंक मार्गो पर बसे चलाने के लिाए बसे परमिट देने का निर्णय लिया हैं ऐसे परमिट देने सम्बन्धी प्रक्रिया की अब अन्तिम रूप दे दिया गया है और भाीघ्र ही ये सहकारी समितियो अपनी बसे चलाना आरम्भ कर देगी।

राज्य मे 68 आधुनिक बस अडडे है और इस समय 9 बसे अडडे निर्माणधीन है। हमारा भाीघ्र ही कालानौर, रोहतक बाईपास, अम्बाला छावानी और राजौद मे बसे अडडो का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास

सरकार यह मानती है कि यधति हमे कृशि उत्पादन तथा उत्पादकता मे वृद्धि के प्रयास जारी रखने है तथाति केवल

इसी से ग्रामीण निर्धनता दूर नही हो सकती। हमने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए अनेक क्षेत्रीय कार्य्क्रम आरम्भ किये है और इन कार्यकमो के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने पर हम वि ोश बल दे रहे है। इन मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहन रोजगार योजना और हाल ही मे आरम्भ की गई रोजगार आ वासन योजना स्कीम भाामिल है। भौगोलिक दृश्टि से पिछडे क्षेत्रो मे सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूस्लि विकास कार्य{मो को कार्यानिव्त किया जा रहा है। वर्श के दौरान दिसम्बार 1993 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतर्गत 14828 परिवारो को सहायता दी गई है और ट्राईसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्व रोजगार के लिए 3380 ग्रमीण युवको को प्र ाक्षित किया गया और जवाहर रोजगार योजना के अन्तगर्त लाभकारी रोजगार के 12.06 लाख श्रम दिवस जुटाए गए है। राज्य मे 20 सुत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की गति को काफी तेज करने के लिए वर्श 1994–95 मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भवित क्षेत्र कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के लिए कुल 74.97 करोड रूपये का उपबन्ध किया जा रहा है। जो कि इन गतिविधियो हेतु चालू वर्श के 51.77 करोड रूपये के परिव्यय से लगभग 45 प्रति ात अधिक है। हेतु चालू वर्श के 51.77 करोड रूपये के परिव्यय से लगभग 45 प्रति ात अधिक है।

भाहरी विकास

हमारी सरकार भाहरी क्षेत्रो के अनुरक्षण और विकास की और भी इतनी ही जागरूक है। हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण भाहरी क्षेत्रो के योजनाबद्ध एवम एकीकृत विकास का कार्यक्रम रहा है। वर्श के दौरान दिसम्बर 1993 तक हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण ने भाहरी विकास निमार्ण कार्यो पर 44. 45 करोड रूपये खर्च किए और विभिन्न सम्पदाओ मे 8 रिहाय ी तथा 3 औधोगिक सैक्टर बनाए। विभिन्न नगरपालिकाओ को वितीय सहायता देने के चालू वर्श के दौरान 6.55 करोड रूपये वे उपबन्ध के मुकाबले वर्श 1994–95 मे 7 करोड रूपये का उपबन्ध किया जा रहा है। गंदी बस्तियो के सुधार की स्कीम को लागू करने पर वि ोश ध्यान दिया जा रहा है। और वर्श 1994–95 मे गंदी बस्तियो मे रहने वाले 48190 लोगो की सहायता करने के लिए 2.53 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। चालू वर्श मे 3 नई स्कीमें लघु एवम मध्यम दर्जे के नगरो का एकीकृत विकास, निर्धनो के लिए भाहरी बुनियादी सेवाए तथा भाहरी क्षेत्रो मे ि ाक्षित बेरोजगारो के लिए रोजगार जुटाने की स्कीम को भाुरू किया गया है। वर्श 1994–95 के दौरान इन स्कीमो के लिए 2.90 करोड रूपये की रा ि ा की व्यवस्था की गई है। नेहरू रोजगार योजना के लिए वर्श 1994–95 मे उपबन्ध को बढाकर 4.40 करोड रूपये कर दिये गया है।

पिछडा क्षेत्र विकास

मेवात क्षेत्र के विकास के लिए वर्श 1980 मे गठित मेवात विकास बोर्ड इस क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। वर्श 1992–93 तक इस प्रयोजन के लिए 28 करोड रूपये की रा ि ा खर्च की जा चुकी है। मेवात क्षेत्र के विकास के लिए वर्श 1994–95 मे 3.74 करोड रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

अम्बालार जिले मे मोरनी, पिजौर, बरवाला, रायपुर रानी और नारायणगढ खण्डो तथा यमुनानगर जिले के छदरोली, सढौरा तथा बिलासपुर खण्डो मे पर्वतीय और अर्धपर्वतीय क्षेत्रो मे भाीघ्र और एकीकृत विकास के लिए मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता मे ि ावालिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए चालू वर्श के दौरान 2 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है व वर्श 1994–95 के दौरान 3 करोड रूपये का उपबन्ध किया जा रहा है।

विकेन्द्रीकृत योजना

माननीय सदस्य जानते ही है कि पिछले कई वर्शो से राज्य सरकार विकेन्द्रीकृत योजना स्कीम को लागू कर रही है। स्थानीय स्कीम के विकास कार्य जिला स्तर पर किए जाते है। स्कीमे जिला योजनाए बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है जिनमे अध्यक्षर के तौर पर उपायुक्त, स्थानीय अधिकारी, जन नेता, विधायक तथा सांसद भाामिल होते है। इन स्कीमो को तैयार करने मे जनता के

प्रतिनिधियो को और नजदीक से भाामिल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भविश्य मे प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मे ऐसे विकास कार्य स्थानिय विधायक के निर्दे ाो के अनुसार किए जाएगे। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक विधान सभा विर्वाचन क्षेत्र के लिए 20 लाख रूपये का प्रवाधन किया जाएगा। मुझे पूरा वि वास है कि ऐसा करने मे माननीय सदस्य अपने चुनाव क्षेत्रो के अत्यधिक जरूरी विकास कार्य करवा पाएगे।

रोजगार

सभी विकास कार्यो का एक मुख्य उद्दे ाय रोजगार जुटाना है हमारी सरकार सगठित तथा असगठित दोनो क्षेत्रो मे वि ोशकर सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर पिछडे वर्गो के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के लिए वचनबद्ध है। नेहरू रोजगार योजना, जवाहन रोजगार योजना, ट्राइसेम और ड्वाकरा जैसी विभिन्न स्कीमो के माध्यम से इस दि ाा मे भरसक प्रयत्न किए जा रहे है। आठवी योजना के दौरान एक परिवार एक रोजगार स्कीम के अन्तर्गत रोजगार के पाच लाख अवसर जुटाने का हमारा प्रस्ताव है। वर्श 1992–93 के दौरान, प्राइवेट सैक्टर मे 31526 स्वरोजगार सैक्टर मे 73794 तथा श्रम रोजगार सैक्टर मे 66941 व्यक्तियो की स्वरोजगार के लिए प्रि ाक्षित किया गया। बेरोजगारी भता स्कीम के अन्तर्गत वर्श 1994–95 के दौरान 3.35 करोड रूपये 35000 पात्र बेरोजगार व्यक्तियो मे वितरित किए जाएगे। बरवाला मे एक नया ग्रामीण रोजगार केन्द्र खोल कर और महेन्द्रगढ तथा

नारायणगढ मे दो रोजगार केन्द्रो का दर्जा बढा कर राज्य के 95 रोजगार केन्द्रो के वर्तमान नेटवर्क का सुदृढ किया जा रहा है। खेती बाडी की मंदी के दौरान 18 से 60 वर्श के आयु वर्ग के व्यक्तियो के लिए कम से कम 100 दिना का रोजगार सुनि चत कराने के लिए सरकार ने नवम्बार 1993 मे रोजगार आ वासन स्कीम भुरू की। भारत सरकार के साथ भागीदारी आधार पर राज्य के 44 खण्डो मे यह स्कीम लागू की जा रही है। वर्श 1993–94 मे इस के लिए 16.50 करोड रूपये की रा ि ा खर्च की जा रही है। और वर्श 1994–95 मे 30.50 करोड रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

औधोगिक प्र ि ाक्षण

उधोगीकरण का लाभ तब तक पूरी तरह से नही उठाया जा सकता जब तक राज्य मे उधोगो के लिए प्र ि ाक्षित व्यक्ति उपलब्ध न हो। 140 औधोगिक प्र ि ाक्षण सस्थानो और व्यावसायिक प्र ि ाक्षण सस्थानो की एक व्यापक स्ाापना द्वारा 70 से ज्यादा ट्रेडो और व्यवसायो मे प्रति वर्श 10000 युवको को प्र ि ाक्षण दिया जाता है। ि ावालिक विकास बोर्ड के तत्वावधान मे कालका, बरवाला और सढौरा मे तीन नये औधोगिक प्र ि ाक्षण सस्थान स्थापित किए जा रहे है। वर्श 1994–95 के दौरान औधेगिक प्र ि ाक्षण के लिए 7.62 करोड रूपये की रा ि ा का प्रावधान किया गया है। हायर सैकण्डरी ि ाक्षा को व्यावसायिक बनाने के लिए 1993–94 मे 5.27 करोड रूपये के योजनागत

उपबन्ध को बढाकर वर्श 1994–95 के लिए 6.46 करोड रूपये कर दिया गया है। आगामी वर्श मे 10 नये व्यावसायिक प्र ि ाक्षण सस्थान स्थापित किये जाएगे।

तकनीकी ि ाक्षा

मानव संसाधान विकास के एक अहम अंग के रूप मे सरकार तकनीकी ि ाक्षा को सदैव महत्व देती रही है। अत हम ने प्रत्येक जिला मे कम से कम एक पालिटैक्निक स्थापित करने का निर्णय लियाा है। जिला गुडगाव मे मानेसर मे एक राजकीय पालिटिक्नक स्थापित करने की योजना है। जिसके लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया हैं हिसार मे राज्य का तीसरा इजीनियरिग कालेज खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। और दो विशयो मे अस्थायी तौर पर ि ाक्षा आरम्भ भी कर दी गयी है। राजकीय और गैर सरकारी पालिटैन्निक सस्थानो को आधुनिक और सुदृढ बनाने के लिए एक वि ोश बैक परियोजना लागू की जा रही है ंहिसार फरीदाबाद, उटावड और नारनौल मे चारे नये पालिटैक्निक सस्थांन 32 करोड रूपये की अनुमानित लागत से स्थापित किये जा रहे है। वर्श 1994–95 के दौरान तकनीकी ि ाक्षा के लिए 38.97 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।

हम नये प्रोधोगिकी के लाभ ग्रामीण क्षेत्रो तक पहुचाने के लिए राज्य के सभी पाालिटैक्निक सस्थाओ सामुदायिक पालिटैक्निक स्कीम भाुरू कर रहे है। राज्य मे 8 पालिटैक्निक

सस्थानो को सामुदायिक पालिटैक्निक घोशित किया गया है। ये सस्थान विज्ञान तथा तकनीकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास कार्य करेग।

सरकार ने 80 लाख रूपये की लागत से राश्ट्रीय विज्ञान सग्रहालय परिशद के सहयोग से हिसार मे उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णया लिया है। चालू वर्श के दौरान प्राकृतिक साधन आकडा प्रबनध प्रणाली नामक एक एक परियोजना भाुरू की गई है।

ि ाक्षा

मानव संसाधनो के प्रभावी विकास के लिए सरकार ने ि ाक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी है। यह महसूस करते हुए जीवन के स्तर मे सुधार और प्रतिश्ठता के लिए ि ाक्षा और साक्षरता आव यक है, आठवी पचवर्शीय योजना के अत तक प्राथमिक ि ाक्षा को सब लोगो तक पहुचाने और पूर्ण साक्षरता का महत्वकाक्षी लक्ष्य नि चत किया गया है। ग्राम स्तर पर इस कार्य के लिए ग्राम पचायतो को भी भाामिल किया गया है। बीच मे स्कूल छोड कर जाने वाल और स्कूल न जाने वाले बच्चो को दाखित करने मे वि ाश्ट कार्य करने के लिए प्रत्येक खण्ड मे एक पचायत और एक विधालय चुना जाता है। ऐसी 124 पचायतो और विधालयो को पाच पाच हजार रूपये का नकद पुरस्कार दिया गया। प्राथमिक विधालयो मे 6 से 11 वर्श के आयु वर्ग के स्कूल

न जाने वाले और स्कूल छोड जाने वाले अधिक से अधिक बच्चो को दाखिल करने के लिए वि ोश दाखिला अभियान चलाया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक विधालयो मे पढने वाले बच्चो की संख्या 22.40 लाख हो गई है। 900 से अधिक जे0बी0टी0 टीचर को नियुक्त किया गया है और 1256 जे0बी0टी0 अध्यापको को प्राथमिक विधालयो मे मुख्याध्यापक के रूप मे पदोन्नद किया गया ।

अम्बाला, यमुनानगर, जीन्द, भिवानी, रोहतक, और सिरसा जिलो मे पूर्ण साक्षरता परियोजनाए चलाई जा रही है। इन परिजयोनओ को मार्च, 1994 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव है। इसके बाद उतर साक्षरता कार्यकम भुारू किया जाएगा। पानीपत जिला मे उतर साक्षरता अभियान चल रहा हैं आठवी पचवर्शीया योजना के अन्त तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भोश जिलो मे उपायुक्त वातावरण बनाने का अभियान भुारू किया जा चुका है।

वर्श के दौरान, 31 प्राथमिक, 32 मिडल और 22 उच्च विधालयो का दर्जा बढाया जा रहा है। अध्यपाको की कमी को पूरा करने के लिए अध्यपको के 150 पद व प्राध्यपको के 250 पद भी बनाये गये है। वर्श 1994–95 के दौरान 50 प्राथमिक और 25 मिडल विधालय का दर्जा बढाया जायेगा और 200 अध्यापको तथा 250 प्राध्यपको को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

प्राथमिक ि ाक्षा मे सुधार लाने के लिए 8 जिला ि ाक्षण एवम प्रि ाक्षण सस्थानो की स्थापना की गई है। और वर्श 199़4.95 के दौरान 4 अन्य ऐसी सस्थाए स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य मे 9 जवाहर नवोदय विधालय चल रहे है और 3 ऐसे अन्य विधालय कुरूक्षेत्र, गुडगाव और रेवाडी जिलो के लिए स्पीकृत किए गए हैं वर्श 1994–95 के दौरान 2 और जवाहर महोदय विधालय खोलने का प्रस्ताव है।

विधालय भवनो की मरम्मत करने तथा अतिरिक्त श्रेणी कक्षो के निर्माण के लिए वि ोश अभियान चलाया गया है। वर्श 1993–94 के दौरान 401 विधालय भवनो की मरमत तथा 287 क्षेणी कक्षाओ का निर्माण क्रम ा 1.29 करोड रूपये तथा 2.14 करोड रूपये की लागत से किया गया है। विधालय भवनो की मरम्मत तथा निमार्ण की स्कीम आगामी वर्श भी जारी रखी जाएगी।

प्राथमिक तथा विधालय ि ाक्षा को महत्वपूर्ण समझने के साथ साथ सरकार द्वारा उच्चतर ि ाक्षा को अधिक गति ील तथा गहन बनाने के भी प्रयत्न किए जा रहे है। तदनुसार चालु वर्श के दौरान एक नया राजकीय महाविधालय बरवाला मे व दो नये गैर सरकारी महाविधालय पजीखडा अम्बाला तथा समालखा पानीपत मे खोले गये है। वर्श 1994–95 मे तौ ाम भिवानी मे गैर सरकारी महाविधालय खोलने के लिए भी अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया है अध्यापक प्रि ाक्षण कार्यक्रम को पूर्ण रूप से

बदला गया है ताकि राश्ट्रीय ि ाक्षा नीतिका प्रभावी कार्यान्वययन हो सके। प्राध्यापको और ि ाक्षा प्र ाासको के लिए विभिन्न कार्य ाालाए तथा गोश्ठियो का आयोजन किया गया है। वि वविधालय अनुदान आयोग के दि ाा निर्दे ाो के अनुसार उच्चतर ि ाक्षा के क्षेत्र मे सुयोग्य प्राध्यापको की भर्ती के लिए वि वविधालय अनुदान आयोग द्वारा स्पीकृत राश्ट्र स्तरीय पात्रता परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। विधार्थीयो की सख्या मे वृद्धि के कारण अध्यापको की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्राध्यपको के 25 पद बनाए गए है तथा 200 प्राध्यपको को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हैं माहला ि ाक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उच्चतर ि ाक्षा निदे ाालय मे एक महिल कक्ष की सीापना की गई है सरकार वि वविधालय ि ाक्षा की और भी इतना ही ध्यान दे रही है।

स्वास्थय

सरकार 2000 ई0 तक सभी के लिए स्वास्थय के उददे ाय को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। 134 स्वास्थय केन्द्रो, 45 प्राथमिक स्वाास्थय केन्द्रो, 22 सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र और 4 हस्पतालो का निर्माण करके स्वास्थय सेवाओ का विस्तार किया जा रहा हे। इससे राज्य मे सभी को 5–6 किलोमीटर के घेरे मे चिकित्सा और स्वास्थय सुविधाए उपलब्ध हो जायेगी। परिवार कल्याण और जनसख्या नियन्त्रण कार्यक्रमो के परिणाम अच्छे उपलब्ध हो जायेगी। परिवार कल्याणा और

जनसख्या नियन्त्रण कार्यक्रमो के परिणाम अच्छे रहे है। और जन्म दर और ि ा ु मुत्यु दर कम हो कर क्रम ाः 31.9 और 75 प्रति हजार हो गई है, जो 2000 इस्वी तक 21 और 60 प्रति हजार तक और कम हो जाने की सम्भावना है। हमारा प्रस्ताव है कि माता व ि ा ु की देखभाल के लिए प्रसव व उससे पूर्व और प चात की रोग निरोधी तथा प्रतिरक्षण सेवाए बढाई जाए। औरल री हाईड्रे ान थैरपी और गम्भीर भवास सक्रमण नियत्रण सम्बन्धी दो नये कार्यक्रमो भुरू किये गये है। एक राज्य स्वास्थय तथा परिवार कल्याण संस्थान, पचकूला मे स्थापित किया गया हैं। एडस के बढते हुए खतरे पर काबू पाने के चालू वर्श के दौरान 44.48 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की जा रही है। ताकि लोगो को, वि ोश कर रोग सम्भावित वर्गो को, इस के प्रति सचेत किया जा सके।

औधोगिक कामगारो को भी अधिक स्वास्थय सेवाए उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। इसके लिए भिवानी मे 50 बिस्तर का ई0एस0आई0 हस्पताल और रोजका मेव, गुडगाव मे एक ई0एस0आई0 डिस्पैसरी खोली जाएगी। रोहतक मैडिकल कालेज तथा हस्पताल मे तपेदिक और छाती की बीमारियो के लिए 50 बिस्तरो वाला वार्ड और अति वि ि ाश्ट सेवाओ के लिए एक नया खंड बनया जा रहा है। जहां चार उन्नत क्षेत्रो मे अति वि ि ाश्ट सेवाए प्रदान की जायेगी। पचकुला मे हरियाणा वैकल्पिक चिकित्सा तथा अनुसधान संस्थान परिशद स्थापित की गई है ताकि आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक प्रणालियो जैसी वैकल्पिक

चिकित्सा प्रणालियो को प्रोत्साहन दिया जा सके। हम वर्श 1993–94 के दौरान 10 नई आयुर्वेदिक डिस्पैसरिया और वर्श 1994–95 के दौरान ऐसी पांच नई डिस्पैसरिया खोल रहे है। श्री कृश्ण राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवम हस्तपाल कुरूक्षेत्र के भवन के निर्माण कार्य मे लगातार प्रगति हो रही है।

जल सप्लाई एवम सफाई

अच्छी सेहत के लिए स्वच्छ पेय जल बहुत जरूरी है राज्य के सभी 6745 गावो मे स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने के बाद अब हमने गावो मे प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता बढाने के काम पर जोर दिया है। चालू वर्श तथा अगले वर्श 800 ऐसे गावो को इस योजना के तहत लाया जाएगा। आठवी पचवर्शीय योजना के अन्त तक गावो की सभी ढाणियो को पेय जल की सुविधाए जुटा दी जायेगी।

वर्श 1994–95 के लिए इस प्रयोजनार्थ 2 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। चालू वर्श के दौरान 9 बडे गावो मे घरो मे पानी के कनैक ान देने के लिए मौजूदा जल सप्लाई को बढाया जाएगा। अगले वर्श तीन और बडे गावो मे इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। 42 करोड रूपए की लागत से किफायती ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के तहत एक लाख से ज्यादा ग्रामीण घरो मे पानी वाले फल ा भौचालय बनाए गए है।

सरकार भाहरी क्षेत्रो मे भी जल सप्लाई और सफाई की जरूरत के प्रति पूरी तरह जागरूक है। भाहरो में इन सुविधाओ को सुधारने के लिए परिव्यय मे 16.5 प्रति ात की बढौतरी की गई है। बहादुरगढ और गुडगाव भाहरो को पेय जल सप्लाई करने के लिए 40 करोड रूपए की लागत से एक अलग जल वाहक नहर का निर्माण कार्य भीघ्र पूरा होने की सम्भावना है। तीन भाहरो मे बरसाती पानी के निकास के लिए नालियो की और हिसार मे सालिड वेस्ट को निपटाने की व्यवस्था के लिए भी कार्य आरम्भ किया गया है। सरकार ने 133.47 करोड रूपए की लागत से यमुना नदी की सीमा के साथ लगते सात भाहरो मे पूर्ण सफाई और मल ाोधन सुविधा का प्रबन्ध करने का एक महत्वकाक्षी प्रोग्राम भाुरू किया है। यह प्रोग्रोम केन्द्रीय सरकार के साथ मिल कर पूरा किया जाएगा और इसके लिए ओ0सी0ई0एफ0 जापान द्वारा रा ि ा जुटाई जाएगी।

कमजोर वर्गो का कल्याण

हमने समाज के कमजोर वर्गो, वि ोशतया अनुसूचित जातियो और पिछडे वर्गो के विकास पर वि ाश जोर दिया है। यधपि सामान्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमो मे, जिनके बारे मे पहले ही बता चुका हू समाज के इन वर्गो की और वि ोश ध्यान दिया जाता है तथापि हम समझते है कि उनके उत्थान के लिए और अधिक प्रयत्न करने की आव यकता है। साधारण को बढाव देने और समाज के कमजोर वर्गो के बच्चो के ि ाक्षा उपलब्ध करवाने

के लिए अनेक स्कीमे लागू की जा रही है। अनुसूचित जाति की विधवओ की पुत्रियो के विवाह पर दी जातनी वाली आर्थिक सहायता 5000 रूपये से बढा कर 10000 रूपये कर दी गई है। इसी प्रकार अत्यचारो के ि ाकार व्यक्तियो के नजदीकी सम्बन्धियो को दी जाने वाल वितीय राहत मृत्यु के मामले मे 10000 रूपए से बढाकर 25000 रूपए कर दी गई है। 20 सुत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनो को आवास स्लि अलाट करने की स्कीम के अन्तर्गत वर्श 1974 और 1982 के सर्वेक्षण मे अकित सभी पात्र व्यक्तियो को आवास स्लि अलाट किए जा चुके है। इससे अनुसूचित जाति के लगभग 3 लाख परिवारो को लाभ पहुचा है।

हरियाणा हरिजन कल्याणा निगम अनुसूचित जातियो के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस निगम को प्राधिकृत पून्जी बढाकर 20 करोड रूपए कर दी गयी है।

अनुसूचित जातियो की वि ोश सघटक योजना के अन्तर्गत वर्श 1994–95 के कुल योजना परिव्यय का 13.9 प्रति ात अनुसूचित जातियो के परिवारो को सीधे लाभ देने वाली स्कीमो के लिए निर्धारित किया गया है।

भूतपूर्व सैनिको का कल्याण

माननीय सदस्य जानते है कि भूतपूर्व सैनिक हमारे समाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण भंग है। हमारे राज्य का प्राय हर नौवा व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक के परिवार से है। यह बात दे ा की

सीमाओ की रक्षा मे हरियाणा द्वारा दी गई महान सेवा की सूचक है। राश्ट्रीय सुरक्षा मे उनके योगदान को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने भूतपूर्व सैनिको को अनेक रियासते दी है चालू वर्श के दौरान उनके कल्याणा के लिए 5 करोड रूपए से अधिक रा ि ा खर्च की जा रही हैं भूतपूर्व सैनिको के हितो की रक्षा हेतू सरकार की चार नए जिलो, रिवाडी, कैथल, पानीपत और यमुनानगर मे जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने की योजना है। अस्थलबोहर मे एक राज्य युद्ध स्मारक हाल बनाया जा रहा है। रोहतक मे मातनहेल और रिवाडी मे पालीगोदार मे दो नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। रिवाडी मे एक भर्ती कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा गया है।

महिलाए बच्चे तथा समाज कल्याण

महिलाओ को अपनी भाक्ति पहचानने के समर्थ बनाने व उन्हे विकास की प्रक्रिया मे भागिल करने के लिए हम वचनबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ वर्श 1992 मे महिला तथा बाल विकास नाम एक अलग विभाग स्थापित किया गया। वर्श 1994–95 मे यू0ए0एफ0पी0ए0 की सहायता से सरकार 37.64 करोड रूपए की लागत से ''महिला एम्पावरमैट व समेकित विकास'' परियोजना आरम्भ कर रही है। एकीकृत बाल विकास योजना, जो कि इस समय राज्य के 107 खण्डो मे लागू की जा रही है। को राज्य के भोश सभी खडो मे लागू करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए हर्श हो रहा है कि हरियाणा दे ा मे एकमात्र

ऐसा राज्य होगा जिसके सभी ग्रामीण खंडो मे एकीकृत बाल विकास योजना चालू है। इस योजना के स्तर मे गुणात्मक सुधार लाने के उददे ाय से राज्य के सभी आगनबाडी वर्करो को ि ाक्षण प्रणाली तथा विधालय पूर्व की गतिविधियो मे रिफ्रै ार प्रि ाक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अकुर नाम ही एक पुस्तिका पहले से ही तैयार की जा रही है।।

वर्श 1994–95 के दौरान 122.13 करोड रूपए के परिव्यय से सामाजिक रक्षा तथा सुरक्षा की अन्य स्कीमो को भी जारी रखा जाएगा। इन स्कीमो मे निराश्रित एवम पीडित महिलाओ के लिए वि ोश परियोजनाए, अपंग छात्रा के लिए छात्रवृतियो, विधवाओ, अपंग व्यक्तियो और राज्य के वरिश्ठ नागरिको के लिए सुरक्षा भत्ता भी भाामिल है।

आवास

सरकारी भाहरी तथा ग्रामीण निर्धन व्यक्त्यो के लिए आवास की आव यकता के प्रति पूरी तरह सजग है। तदनुसार हमने वर्श 1994–95 मे आवास के प्रावधान को बजट अनुमान 1993–94 की तुलना मे 75 प्रति ात बढा दिया है। चालू वर्श के उपबन्ध को भी 20 प्रति ात बढाकर 33.67 करोड रूपये कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लोगो के लिए ऋण योजना के अन्तर्गत इस वर्श बाढ के दौरान क्षतिग्रस्त मकानो की

मरम्मत के लिए हुडको द्वारा 8.71 करोड रूपए के राहत ऋण दिए गए।

राज्य के विभिन्न सीलो पर आवास यूनिटो के निर्माण के लिए चालू वर्श के दौरान आवास बोर्ड द्वारा 84.36 करोड रूपए खर्च किए जाएगे। बोर्ड की, हुडको के सहयोग से कम लागत वाली निर्माण तकनीको का प्रयोग करते रूपए 500 मकान बनाने की भी योजना है।

राजस्व प्र ाासन

भू अभिलेखो की व्यवस्था करना राजस्व प्र ाासन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यो मे से है। हमारी सरकार ने भूमि तथा राजस्व प्र ाासन के आधुनिकीकरण और सुधार की और काफी ध्यान दिया है। रिवाडी जिले मे भूमि अभिलेखो का कम्पयूटरीकरण करने की एक पायलट परियोजना भ्रारू की गई है। भू अभिलेखो की क्मपयूटरीकरण व्यवस्था करने के लिए रोहतक, हिसार, सिरसा, गुडगाव जिलो मे कम्पयूटर केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुकी है। राजस्व अभिलेखो की सुरक्षा के लिए वर्श 1993–94 मे पांच रिकार्ड रूमो का निर्माण किया जा रहा है। हिसार मे लघु सचिवालय बनाने के कार्य पूरा हो चुका है। यमुनानगर, कैथन, और रिवाडी मे मे लघु सचिवालय बनाने के कार्य वर्श 1994–95 मे भ्रारू किया जाएगा। राज्य मे 472 पटवारखाने मौजूद है और 242 अन्य पटवारखाने निर्माणाधीन है

जनता की सुविधा के लिए सभी 3136 पटवार सर्कलो मे पटवारखाने बनाए जाने का प्रस्ताव है।

खजाने

हरियाणा मे वितीय व्यवस्था का स्तर हमे ा बहुत बढिया रहा है। वितीय व्यवस्था को और कु ाल बनाने के उदे य से राज्य के सभी खजानो का कम्पयूटीकरण किया जा रहा है। आठ नए उप खजानो को स्थापित करके राज्य मे विदयामान 18 जिला स्तरीय खजानो व 77 उप खजानो के नैटवर्क को सुदृढ बनाने का प्रस्ताव है।

प्राइवेट लाटरियो पर प्रतिबन्ध

चालू वर्श मे लाटरी व्यापार मे अभूतपूर्व विस्तार हुआ है जनसाधारण की बेईमानी लाटरी आयोजको के हाथो धोखे तथा ठगो की सभावना से बचाने के लिए राज्य विधानमण्डल ने हरियाणा प्राईवेट लाटरी निशेध अधिनियम 1993 बनाया है। इससे हरियाणा क्षेत्र मे आयोजको द्वारा चलाई जा रही सभी लाटरियो की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अब केवल राज्य सरकार द्वारा स्वय आयोजित लाटरिया ही हरियाणा मे बेची जा सकती है। राज्य का लाटरी विभाग राज्य मे विकास कार्यो के लिए संसाधन जुटाने हेतु अनेक लाटरी स्कीमो को चला रहा है। विभाग का निवल लाभ 6.27 करोड रूपए के बजट अनुमानो से बढकर 14.55 करोड रूपए होने की आ ाा है।

सरकारी कर्मचारियो को रियायते

हरियणा के सरकारी कर्मचारियो ने राज्य के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनहे प्रोत्साहन देने तथा उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए चालू वर्श के दौरान सरकारी कर्मचारियो को अनेंक रियायते दी गई।

माननीय सदस्यगण जानते है कि भारत सरकार ने पाचवा वेतन आयोग गठित किया है और इस की सिफारि ा पर अपने सभी कर्मचारियो के 100 रूपए प्रतिमास की अत्तरिम राहत दी है। हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियो के लिए इसी प्रकार अत्तरिम राहत दे दी है। इस से राज्य के कोश पर 31 करोड रूपये का वार्शिक भार पडने की सभावना है । वर्श 1992–93 के दौरान, राज्य सरकार ने 8 और 18 वर्श की नियमित सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की स्कीमे चलाई थी। इस स्कीम के स्थान पर ग्रप सी तथा ग्रुप डी के सभी कर्मचारियो को 10 तथा 20 वर्श की नियमित सेवा पूरी करने के प चात उच्चतर मानक वेतनमान देने की अधिक उदार स्कीम बनाई गई है। राज्य मे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो को पहली अप्रैल, 1994 से 60 रू0 प्रतिमास की दर पर वर्दी भता नकद दिये जाने की अनुमति दी गई है। कर्मचारियो को मिलने वाले निि चत चिकित्सा प्रतिपूर्ति भते की दर 45 रूपये प्रतिमास से बढाकर 60 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। माननीय सदस्यगण इस बात को

मानेगे कि राज्य के वितीय संसाधनो की सीमा मे ही हम ने सरकारी कर्मचारियो को पर्याप्त राहत दी है।

स ाोधित अनुमान 1993–94

मैने पहले भी कहा है कि चालू वर्श के दौरान सरकार को भारी वितीय कठिनाईयो का सामना करना पडा। बाढ से हुई क्षति, बाजार मे मंदी और बिजली की चिन्ताजनक स्थिति से हमारी राजस्व प्राप्तियो पर प्रभाव पडा और परिणामस्वरूप अतिरिक्त खर्च हुआ। कर राजस्व 1993–94 के बजट अनुमानो मे द ाोए गए 2003.42 करोड रूपए से कम होकर स ाोधित अनुमानो मे 1893. 98 करोड रूपये रह गया। इस मे केन्द्रीय सरकार की सूचना अनुसार केन्द्रीय करो मे राज्य के हिस्से मे 24.66 करोड रूपये, पथा कर के समाप्त होने के कारण वाहन करो के अन्तर्गत वसूली मे 27 करोड रूपए और मदिरापान के विरूद्ध राज्य के कुछ भागो मे आदोलन होने से उत्पादन भाुल्क मे 46 करोड रूपये की मुख्य कमी हुई। खर्च पक्ष मे, जल सप्लाई स्कीम के रख रखाव पर 11 करोड रूपये, महालेखाकार के परमा र्ा के अनुसार पै ान सम्बन्धी देयताओ मे 18.65 करोड रूपय तथा ब्याज अदयगियो मे 6.25 करोड रूपये की वृद्धि हुई । सरकारी कर्मचारियो को दी गई विभिन्न रियायतो, जिन का उल्लेख पहले किया जा चुका है। का भी राजकोश पर काफी बोझ पडा है। हमने राजस्व खर्च पर कडा नियन्त्रण रखा है और जैसा कि माननीय सदस्य देखेगे कि केवल अत्याधिक महत्व वाले अतिआव वयक मदो पर ही खर्च करने की

स्वीकृति दी गई है। कुल योजननगत परिव्यय को स ाोधित अनुमानो मे 920 करोड रूपये से घटा कर 831.46 करोड रूपये करना पडा। तथापि, यह सुनि चत कर लिया गया कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रो और निर्धारित क्षेत्रो के योजनागत परिव्यय का बरकरार रखा जाए ताकि राज्य के समूचे विकास पर इसका प्रभाव न पडे।

पिछले वित वर्श के दौरान सरकार की अच्छी वित व्यवस्था के परिणामस्वरूप वर्श 1993–94 का आरम्भिक घाटा 54.27 करोड रूपये रहा जबकि बजट अनुमानो मे यह घाटा 81.37 करोड रूपये अनुमानित था। बजट अनुमान 1993–94 को इस गरिमामय सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के बाद उभरने वाले सभी हालात को ध्यान मे रखते हुए स ाोधित अनुमान द ार्शाते है कि भारतीय रिजर्व बैक के खातो के अनुसार चालू वित वर्श 74.48 करोड रूपये का घाटा परियोजित था। वितीय घाटा, चालू वर्श के राज्य गृह उत्पाद के लगभग 3 प्रति ात तक होने की सभावना है जो कि सीमाओ के अन्दर ही है।

बजट अनुमान 1994–95

माननी अध्यक्ष महोदय, अब मै इस गरिममामय सदन मे वर्श 1994–95 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हू। निम्नलिखित तालिका मे वर्श 1993–94 के स ाोधित अनुमानो और 1994–95

के बजट अनुमानो के अनुसार राज्य सरकार की वितीय स्थिति द र्ाई गई है:–

सघटक	लेखे	बजट अनुमान	स ोधित अनुमान	बजट अनुमान
	1992.93	1993.94	1993.94	1994.95
1	2	3	4	5
I.. अथ भोश				
(क) महोलखाकार के अनुसार	(–) 0.14	(–) 72.85	(–)57.59	(–)77.80
(ख) भारतीय रिजर्व बैक के अनुसार	(–) 8.66	(–) 81.37	(–)54.27	(–)74.48
(ग) खजाना बिलो मे निवे ा	1.50	1.50	17.42	17.42
II. राजस्व लेखा				

प्राप्तियो	2377.64	2872.99	3541.43	4305.82
खर्च	2379.34	2829.32	3533.22	4818.09
अधि ोशघाटा	(–)1.70	(+)43.67	(+)8.21	(+)512.27
III पूजगती खर्च	228.34	255.37	314.46	214.51
IV. लोक ऋण				
लिया गया ऋण	418.92	854.85	789.31	1157.61
भुगतान	163.47	546.82	400.62	813.67
निवल	(+)255.45	(+)308.03	(+)388.69	(+)343.94
Y. कर्ज और पे ागिया				
पे ागिया	245.01	266.98	282.05	322.79
वसूलिया	31.01	34.36	34.90	457.02
निबल	(–)21400	(–)**232.62**	(–)247.15	(+)134.22
VI. लघु बचत				

भविश्य निधि आदि				
निवल	(+)132.35	(+)114.29	(+)162.98	(+)215.08
VII. जमा तथा पे ागिया आरक्षित निधि औा उचन्त तथा विविध				
निवल	(–)3.77	(+)14.05	(–)18.48	(+)36.96
VIII. प्रे ाश				
निवल	(+) 2.56	(+)2.00	0.00	0.00
IX. इति ोश				
(क) महालेखाकार के अनुसार	(–) 57.59	(–) 78.80	(–) 77.80	(–) 74.83
(ख) भारतीय रिजर्व बैक के	(–)54.27	(–)87.32	(–)74.48	(–)71.11

अनुसार				
(ग) खजाना बिलो मे निवे ा	17.42	1.50	17.42	17.42

वर्श 1994–95 रिर्जव बैक के खातो के अनुसार 74.48 करोड के घाटे से भुरू व 71.11 करोड रूपये के घाटे से खत्म होने की सम्भावना है। अत वर्श के खाते मे, चालू वर्श के स ाोधित अनुमानो मे हो रहे 20.21 करोड के घाटे की तुलना मे वर्श 1994–95 मे 3.37 करोड रूपये का अधि ोश होना सभावित है। बजट अनुमानो मे 1025.50 करोड रूपये की राज्य योजना व 231.76 करोड रूपये की केन्द्र चालित व अन्य विकास योजनओ के परिव्यय समेत कुल 1257.26 करोड रूपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

वर्श 1994–95 के राजस्व लेखे और पूजीगत प्राप्तियो पर कुछ घटको का प्रभाव होगा। लाटरी की टिकटो मे चालू वर्श मे जबरदस्त वृद्धि हुई है। अत 1994–95 मे लाटरी की आया 940 करोड रूपये व खर्च 924.47 होने का अनुमान है, जिससे 15.53 करोड रूपये का निवल लाभ होगा। मैने पहले भी कहा है कि सरकारी विभागो के बकाया बिजली बिलो के भुगतान हेतू 425 करोड रूपये का प्रवाधान किया गया है। कृशि क्षेत्र को रियायती बिजली सप्लाई के एवम मे बिजली बोर्ड को दी जाने वाली

सबसिडी के बकाया 350 करोड रूपये के भुगतान का प्रावाधान भी वर्श 1994.95 के बजट अनुमान मे किया गया है। फलस्वरूप 1993. 94 के स ाोधित मे दिखाए गए 8.21 करोड रूपये के राजस्व अधि ोश के मुकाबले 1994–95 के राजस्व लेखे मे 512.27 करोड रूपये का घाटा प्रत्याि ात है। बहरहाल, ग्रास आकडो से 1994–95 मे राज्य के राजस्व लेख की वास्तविक स्थिति का पता नही लग पाता, क्योकि लाटरी की आय व खर्च तथा कर्ज प्राप्तियो के समायोजन के लिए बिजली बोर्ड को बिलो की अदायगी कान्ट्राएटरी है। ऐसी एन्ट्रियो का हिसाब करने के बाद नैट आधार पर 1994–95 मे राजस्व घाटा 32.47 करोड रूपये रह जाता है। 1993.94 के स ाोधित अनुमानो की तुलना मे 1994–95 के बजट अनुमानो मे राजस्व प्राप्तियो ग्रास आाधार पर 764.39 करोड रूपये व नैट आधार पर 328.48 करोड रूपये बढी है। कर राजस्व मे 1993–94 के स ाोधित अनुमानो की तुलना मे वर्श 1994–95 के बजटठ अनुमानो मे 11.35 प्रति ात की वृद्धि है यघपि भिन्न करो के लिए भिन्न वृद्धि दरे अपनाई गई है। केन्द्रीय करो मे हिस्सा भारत सरकार के वित मंत्रालय द्वारा दिये गये सकेतो के अनुसार रखा गया है। नान टैक्स राजस्व मे चालू साल के स ाोधित अनुमानो की तुलना मे 512.39 करोड रूपये की वृद्धि 1994–95 के बजट अनुसार मे मौजूद है। राजस्व प्राप्तियो के अनुमान प्रवृति के आधार पर लगाए गए है व प्राप्तियो के भिन्न साधनो के लिए भिन्न मापदण्ड अपनाए गए है। सम्भव है कि अर्थव्यवस्था मे निहित लचीलेपन व प्रत्याि ात बढौतरी से राजस्व मे और वृद्धि हो पाये।

गैर योजना खर्च का अनुमान लगाने मे प्राय योजना आयोग के अनुदे ाो और नौवे वित्त आयोग की सिफारि ाो को आधार माना गया है आव यक खर्च का प्रावधान करने के प चात योजनतेर राजस्व खर्च को कम से कम रखा गया है।

वर्श 1994–95 के बजट अनुमानो मे सातवी पचवर्शीय योजना तक पूरी की गई स्कीमो के रख रखाव हेतु 57.25 करोड रूपये व खालो को पक्का करने पर हुए खर्च मे लाभ भोगियो के हिस्से की प्रतिपूर्ति हेंतु एम0.आई0टी0सी0 के लिए 14.73 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। जैसे कि पहले कहा गया है कि कृशि क्षेत्र को रियायती बिजली सप्लाई की प्रतिपूर्ति के लिए बोर्ड को 105 करोड रूपये नकद सबसिडी देने का प्रावधान किया गया है। सिचाई व जन स्वास्थय विभागो और एस0आई0टी0सी0 द्वारा वर्तमान बिजली बिलो के भुगतान हेतु 48.68 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग के अनुदे ाो के अनुसार मतदातओ के पहचान पत्र बनाने के लिए 26 करोड रूपये की रा ि ा प्रस्तावति है। सरकारी कर्मचारियो को महगाई भते की जनवरी व जुलाई 1994 मे देय होने वाली दो कि तों के लिए 64. 78 करोड रूपये व 1991.92 व 1992.93 वितीय वर्शो के बोनस की अदायगी के लिए 54.80 करोड रूपये का उपबन्ध बजट अनुमान 1994–95 मे किया गया है।

माननीय सदस्य देखेगे कि 1994–95 के बजट अनुमानो के अनुसार 1157.61 करोड रूपये का सार्वजनिक ऋण राज्य द्वारा

लिया जाएगा। 813.67 करोड रूपये के भुगतान के कारण निवल सार्वजनिक ऋण 343.94 करोड रूपये बढ जाएगा। इन मे केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की और से राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले 27.12 करोड रूपये के बाजारी ऋण भी भामिल है।

मै माननीय सदस्यासे को सूचित करना चाहूगा कि दे ा के कई अन्य राज्यो मे योजना खर्च का एक बडा हिस्सा कर्जे द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन हमारे राज्य मे ऐसा नही है। बहरहाल हमारे राज्य का कुल ऋण भार बढ रहा है। महोलेखाकार, हरियाणा के लेखो के अनुसार 31 मार्च, 1993 को राज्य पर ऋणों का कुल भार 3768.51 करोड रूपये था जो कि हमारी 31 मार्च 1992 की 3300.46 करोड रूपये की ऋण देयता से 14.18 प्रति ात अधिक है। प्रस्तुत स ाोधित अनुमानो के अनुसार राज्य के ऋण भार मे 585.99 करोड रूपये की वृद्धि होगी। अत 31 मार्च, 1994 को राज्य का कुल ऋण भार 4354.50 करोड रूपये हो जाएगा जो 31 मार्च 1993 के मुकाबले 15.6 प्रति ात अधिक होगा। यह भार 31 मार्च, 1995 तक 12.9 प्रति ात की दर से बढकर 4918.11 करोड रूपये होने की सभावना है। यह पूजी मुख्यत पूजीगत निवे ा व उत्पादन भील सम्पति बनाने के लिए है व इन पर ब्याज अदायगी का काफी खर्च होता है। चालू वर्श के सं ाोधित अनुमानो की तुलना मे ब्याज अदायगी का भार, अधिक ऋण प्राप्तियो के कारण बजट अनुमान 1994–95 मे 21.5 प्रति ात

बढ गया है। बजट अनुमानो के अनुसार वर्श 1994–95 के दौरान 535.05 करोड रूपये का ब्याज अदा किया जाएगा।

मै माननीय सदस्यो का याद दिला चाहूगा कि केन्द्र सरकार और अनेक राज्यो का वितीय घाटा काफी अधिक है। वितीय घाटे की उचित सीमाओ मे रखने की आव यकता को अब दे ा मे सभी महत्व देने लगे है। राज्य गृह उत्पाद के अनुपात मे हरियाणा का वितीय घाटा वर्श 1994–95 के दौरान 2.8 प्रति ात तक होने की संभावना है। राज्य के वितीय घाटे को और कम करने के निरतंर प्रयास किए जाएगें

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि अर्थव्यवस्था मे कार्यकु ालता और उत्पादका बढाने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रो मे लाइसैस समाप्त करके और नियत्रण हटाकर उदार नीति अपनाई है। विभिन्न विभागो द्वारा राज्य के प्रदे ा स्थानो अथवा अन्य स्थानो पर बनाये गये बैरियर, जो हालाकि कर की चोरी और सामान एवम वस्तुओ के गैर कानूनी आवागमन को रोकने के आव यक उददे य से ही बनाए गए थे, तथापि इन से यातायात मे रूकावट आती है कु ालता पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है और उत्पादकता मे कमी आती है तथा कीमती समय और ईधन बर्बाद होता है। केन्द्र सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए सरकार ने हरियाणा मे ऐसे सभी नाको को हटाने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप बची जन भाक्ति और अन्य साधनो को कर चोरी रोकने के लिए विभागीय तत्र को स ाक्त बनाने के लिए

उपयोग मे लाया जाएगा। हम समझते है कि इस दे ा मे एकीकृत आर्थिक वातावरण बनने की भुरूआत होगी।

सरकार व्यापक तथा उधोग के सामने आने वाली समस्यओ के प्रति जागरूक है तथा इनके प्रतिनिधियो से लगातार बातचीत कर रही है। उपभोग्ताओ व छोटे व्यावारियो का वि ोशस ध्यान रखते हुए कर प्रणाली मे सुधार और रे ानेलाईजे ान के लिए सरकार द्वारा गहन प्रयास किये जा रहे है। सरकार परे ाानी का कारण बनने वाले सभी प्रोसीजर मे सुधार लाने के लिए भी सदैव तत्पर रहती है। इसी प्रकार मे कुछ कदम हमने उठाए है जिन के विशय मे बताते हुए मुझे प्रस्न्नता हो रही है। 5 लाख रूपये से कम बिक्री वाले छोटे व्यापारियो के लाभ के लिए एक स्कीम प्रस्तावित है। जिनके अन्तर्गत उन्हे घोशित बिक्री के आधार पर देय बिक्री कर की एकमु ात अदयगी की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा से छोटे व्यापरी विस्तृत लेखा जोखा रखने के झझट से बच जाएगे व निर्धारण अधिकारियो को भी बडे व्यापारियो पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की फुरसत मिलेगी। इसी प्रकार की सुविधा जिले के अन्दर नियत मागो पर यात्री सेवाओ के आयोजको को यात्री कर की अदायगी के लिए भी दी जाएगी। हमारे जन समुदाय के निर्धन वर्ग को राहत देने के लिए सरकार का सभी दालों की चूरी व छिलके की, जो कि प ा चारे के रूप मे प्रयोग मे लाए जाते है, बिक्री कर से छुट देने का प्रस्ताव है। तेल व तिलहन के व्यापारी सरकार से इन चीजो पर बिक्री कर

प्रणाली की रै ानेलाईजे ान की मांग करते रहे है। सरकार इस प्रकार की रै ानेलाईजे ान से राज्य के राजस्व पर होने वाले प्रभाव को जांच रही है। बहरहाल हमने तिलहन की अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिए ''सी'' फार्म भरने की भार्त को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। मै यहा कहना चाहूगा कि हमारा उददे ाय वर्तमान कर कानूनो को सख्ती बिना भेदभाव प्रभाव ाली तरीके से लागू करके राज्य के लिए अधिक राजस्व प्राप्त करना है न कि नए कर लगाना अथावा कराधान की दरो मे वृद्धि करना। मेरा इस बजट मे किसी प्रकार के नए कर लगाने का कोई प्रस्ताव नही है।

बजट मे घाटा कम से कम रखा गया है और यह उपयुक्त सीमा के अन्दर ही है। राज्य सरकार ने ''ससाधन और किफायते पर मत्रिमडल उप समिति'' का गठन किया है जिसने काफी आरभिक कार्य कर लिया है। हमे आ ाा है कि खर्चो मे और अधिक कटौती कर के, कर आधार की व्यापाक बना कर, कर प्राप्तियो मे सुधार कर के तथा करो की चोरी को रोक कर हम घाटा और भी कम कर पाएगे। हम योजनेतर खर्च मे भी कमी करने का यत्न करैगे और मुझे वि वास है कि वर्श 1994–95 की वार्शिक योजना मे सभी विकास कार्यक्रमो को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा। इस उददे ाय के लिए मै सभी माननीय सदस्यो तथा हरियाणा की जनता से सहयोग और सहायता की अपेक्षा करता हू।

महोदय, इन भाब्दो के साथ मै बजट अनुमान 1994–95 सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हू।

जय हिन्द

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M tomorrow, the 8th March, 1994.

16.25 hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M on Tuesday, the 8th March, 1994.)